

सांध्य दैनिक

श्रीकंचनपथ

RNI. Reg. No. CHHHIN/2009/30534
डाक पंजीयन क्रं.-छ.ग./दुर्ग/1000000029/2026-28

लीपा पोती नहीं सिर्फ सच

प्रिंट और डीजिटल मीडिया में सभी प्रकार के विज्ञापन के लिए
संपर्क करे
9303289950
7987166110

वर्ष- 18 अंक - 46 | www.shreekanchanpath.com | संस्थापक एवं प्रेरणास्रोत- स्व. श्रीमती रजनी अग्रवाल | भिलाई, रविवार 29 नवम्बर 2026 | पृष्ठ 8- मूल्य 1/-

खास - खबर

क्राइस्टचर्च टेस्ट में न्यूजीलैंड मजबूत, बैकफुट पर टीम इंडिया

क्राइस्टचर्च। न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च में खेले जा रहे टेस्ट मैच के तीसरे दिन न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। पहली पारी में 110 रन की बढ़त हासिल करने के बाद कीवी टीम ने दूसरी पारी में भी दमदार बल्लेबाजी की। दिन का खेल खत्म होने तक न्यूजीलैंड ने 3 विकेट पर 133 रन बना लिए हैं। उसकी कुल बढ़त 243 रन हो गई है। वहीं, भारतीय बल्लेबाजों के निराशाजनक प्रदर्शन ने टीम इंडिया को मुश्किल में डाल दिया है। तीसरे दिन भारत ने अपनी पहली पारी 6 विकेट पर 116 रन से आगे बढ़ाई। ध्रुव जुरेल ने एक छोर संभालते हुए 88 रन की शानदार संघर्षपूर्ण पारी खेली। भारतीय टीम 246 रन पर सिमट गई। भारत की पहली पारी खत्म होने के साथ ही कीवी टीम को 110 रन की अहम बढ़त मिल गई। पहली पारी में बढ़त हासिल करने के बाद न्यूजीलैंड ने दूसरी पारी में भी भारतीय गेंदबाजों को ज्यादा मौके नहीं दिए। हालांकि, भारतीय गेंदबाजों ने तीन विकेट जरूर हासिल किए, लेकिन कीवी बल्लेबाजों ने रन बनाने की गति बनाए रखी। दिन का खेल खत्म होने तक मिचेल 46 रन बनाकर नाबाद लौटे। न्यूजीलैंड ने दूसरी पारी में 3 विकेट के नुकसान पर 133 रन बना लिए हैं।

चार जिलों में रात का पारा 10 डिग्री से नीचे, 5 दिन तापमान में बदलाव के आसार नहीं

रायपुर। छत्तीसगढ़ में ठंड का असर बना हुआ है। प्रदेश के 4 जिलों में रात का तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। इनमें बलरामपुर सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सरगुजा में 8.5, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में 9.8 और सूरजपुर में 9.9 डिग्री तापमान रहा। मौसम विभाग के अनुसार, फिलहाल प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। अगले 5 दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव होने की संभावना नहीं है। देश में न्यूनतम तापमान के आंकड़ों की तुलना करें तो 4 जिलों में पारा 10 डिग्री से नीचे रहा। इनमें बलरामपुर में सबसे कम 8.4 डिग्री, सरगुजा में 8.5 डिग्री, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में 9.8 डिग्री और सूरजपुर में 9.9 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। वहीं, 17 जिलों में न्यूनतम तापमान 10 से 15 डिग्री के बीच रहा। रायपुर में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री दर्ज किया गया। इससे साफहै कि प्रदेश के उत्तरी हिस्से में ठंड का असर ज्यादा है, जबकि मध्य और दक्षिणी हिस्सों में रात का तापमान अधिक बना हुआ है।

बांग्लादेश में हिंसा, अवामी लीग के कार्यकर्ता की हत्या

ढाका। बांग्लादेश में रविवार को फिर हिंसा भड़क गई। इसमें अवामी लीग के एक युवा कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। उसकी मौत सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के कार्यकर्ताओं के साथ हुई झड़प में हुई। यह हिंसा ऐसे समय हुई है, जब पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी ने दो दिन के देशव्यापी बंद का एलान किया है। हसीना को सत्ता से हटाए जाने के बाद यह पार्टी लगातार विरोध कर रही है। देश के कई हिस्सों में देसी बम के धमाकों की रिपोर्ट्स आईं। आगजनी भी हुई। राजमार्ग रोके गए। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बावजूद ये घटनाएं हुईं। हसीना ने 16 दिसंबर को बांग्लादेश लौटने का एलान किया है। इसके बाद सुरक्षा और बढ़ा दी गई है।

परिसीमन से सरगुजा से बस्तर तक बदलेगा छत्तीसगढ़ का राजनीतिक नक्शा : 17 लोकसभा और 135 होंगे विधानसभा

30 नवंबर से 3 दिसंबर तक चलेगा संसद का विशेष सत्र, परिसीमन व महिला आरक्षण को लेकर पेश होंगे अहम बिल

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। केन्द्र सरकार 30 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के विशेष सत्र में परिसीमन और महिला आरक्षण को लेकर बिल पेश करने वाली है। कांग्रेस, सपा व आप सहित अन्य विपक्षी दलों के विरोध के बीच केन्द्र सरकार दोनों बिल पास कराने जरूरी बहुमत जुटाने का प्रयास कर रही है। केन्द्र सरकार की मंशा के अनुसार यदि परिसीमन का प्रस्ताव पास हो जाता है तो इसका असर देश के सभी राज्यों में देखने को मिलेगा। बात यदि छत्तीसगढ़ की जाए तो सरगुजा से बस्तर तक राजनीतिक नक्शा पूरी तरह से बदल जाएगा। परिसीमन के बाद प्रदेश में विधानसभा की सीटें बढ़कर 135 होने की संभावना है। वहीं लोकसभा कीसीटें बढ़कर 16 हो सकती हैं।

बता दें छत्तीसगढ़ विधानसभा में 90 सीटें हैं। इनमें 51 सामान्य, 10 अनुसूचित जाति और 29 अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं। प्रस्तावित 50 प्रतिशत वृद्धि के फार्मूले के अनुसार विधानसभा की सदस्य संख्या 135 तक पहुंच सकती है। प्रस्तावित 135 सदस्यीय विधानसभा में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू होने पर लगभग 45 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो सकती हैं। इस व्यवस्था में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों में भी महिला आरक्षण शामिल होगा। इसका मतलब है कि महिला आरक्षण का प्रभाव रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा, बस्तर, रायगढ़ और कोरबा सहित प्रदेश के सभी क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है।



राजधानी रायपुर, दुर्ग व बिलासपुर में बढ़ सकता है सीटों का दायरा

परिसीमन के बाद सबसे अधिक चर्चा प्रदेश के बड़े शहरी और तेजी से बढ़ती आबादी वाले क्षेत्रों को लेकर है। रायपुर में शहर की मौजूदा विधानसभा सीटों के साथ अभनपुर, धरसींवा और आसपास के क्षेत्रों की सीमाओं में बदलाव हो सकता है। दुर्ग-मिलांई क्षेत्र में दुर्ग शहर, दुर्ग ग्रामीण, मिलाई नगर, वैशाली नगर और अहिवारा सहित आसपास के क्षेत्रों का पुनर्गठन संभव है। इसी तरह बिलासपुर और आसपास के तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्रों में नाए विधानसभा क्षेत्र बनाए जा सकते हैं। जांजगीर-चांपा, रायगढ़, कोरबा, महासमुंद, राजनांदगांव और कवर्धा में भी सीटों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण हो सकता है। सरगुजा और बस्तर संभाग में परिसीमन का असर केवल सीटों की संख्या तक सीमित नहीं रहेगा। यहां जनसंख्या,भौगोलिक विस्तार और आदिवासी क्षेत्रों की परिस्थितियां भी अहम होंगी।

लोकसभा में प्रदेश के 6 नए सांसदों को मिलेगा प्रतिनिधित्व

छत्तीसगढ़ में वर्तमान में लोकसभा की 11 सीटें हैं। प्रस्तावित 50 प्रतिशत वृद्धि के आधार पर इनकी संख्या बढ़कर 16 या 17 हो सकती है। 17 सीटों का आकलन सामने आने से प्रदेश में छह नए सांसदों के प्रतिनिधित्व की संभावना जताई जा रही है। नई संसदीय सीटों के गठन को लेकर रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, सरगुजा और बस्तर जैसे क्षेत्रों का पुनर्गठन चर्चा है। संभावित रूप से रायपुर के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को अलग संसदीय प्रतिनिधित्व देने, दुर्ग-मिलाई के साथ बालोद-बेमेतरा क्षेत्र का पुनर्गठन करने तथा बिलासपुर के साथ मुंगेली-पेंड्रा क्षेत्र को नए स्वरूप में व्यवस्थित करने पर विचार हो सकता है। इसी तरह सरगुजा-अंबिकापुर और जशपुर क्षेत्र तथा बस्तर और दक्षिण बस्तर के बीच संसदीय प्रतिनिधित्व का नया ढांचा तैयार होने की संभावना पर चर्चा हो सकती है।

संभावित 17 लोकसभा सीटों का क्षेत्रीय संतुलन

रायपुर संभाग: मौजूदा समय में रायपुर संभाग के अंतर्गत 2 लोकसभा सीटें (रायपुर, महासमुंद) आती हैं, जिनके बढ़कर 3 से 4 तक जाने के आसार हैं। संभावित नए संसदीय क्षेत्रों में बलौदाबाजार और पुनर्गठित धमतरी प्रमुख रूप से उभर सकते हैं।

दुर्ग संभाग: फिलहाल दुर्ग संभाग में 2 लोकसभा सीटें (दुर्ग, राजनांदगांव) हैं, जो सीटों के विस्तार के बाद 3 से 4 हो सकती हैं। इस अंचल में कवर्धा-बेमेतरा और भिलाई या बालोद को केंद्र बनाकर नए संसदीय क्षेत्रों का खाका खींचा जा सकता है।

बिलासपुर संभाग: इस संभाग में अभी 3 संसदीय क्षेत्र (बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर-चांपा) हैं, जो परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने पर बढ़कर 4 हो सकते हैं। यहां सारंगढ़-रायगढ़ अथवा मुंगेली-लोरमी बेल्ट के पुनर्गठन से एक नई सीट उभरने की प्रबल संभावना है।

सरगुजा संभाग: उत्तर छत्तीसगढ़ के इस संभाग में अभी 2 लोकसभा सीटें (सरगुजा, रायगढ़) मौजूद हैं, जिनके बढ़कर 3 होने की उम्मीद है। जशपुर और कोरिया-सूरजपुर के रूप में दो नए संसदीय क्षेत्रों का विकल्प सबसे मजबूत है।

बस्तर संभाग: वर्तमान में बस्तर संभाग में 2 संसदीय सीटें (बस्तर, कांकेर) हैं, जो नए परिसीमन में बढ़कर 3 हो सकती हैं। यहां दंतेवाड़ा या कोंडागांव को मुख्यालय बनाकर एक तीसरा संसदीय क्षेत्र अस्तित्व में आ सकता है।

विधानसभा में आदिवासी अंचलों में भी बदल सकता है प्रतिनिधित्व

परिसीमन के बाद आदिवासी अंचलों में नए निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाने की संभावना पर चर्चा हो रही है। सरगुजा संभाग में अंबिकापुर, सीतापुर, लुंड्रा, प्रतापपुर और रामानुजगंज जैसे आदिवासी अंचलों की सीमाओं में बदलाव की संभावना है। बस्तर संभाग में जगदलपुर, चित्रकोट, बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोंटा क्षेत्र के प्रतिनिधित्व का नए सिरे से निर्धारण हो सकता है। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या और उनका भौगोलिक वितरण भी परिसीमन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण विषय रहेगा।

जिले अलग अलग संसदीय क्षेत्र में न बंटे इस पर फोकस

परिसीमन आयोग की अंतिम मुहर 2011 की जनगणना के विकासखंड-स्तरीय आंकड़ों और प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं से छेड़छाड़ न करने के बुनियादी नियम पर टिकी होगी। आयोग की प्राथमिकता रहेगी कि किसी भी जिले को दो अलग-अलग संसदीय क्षेत्रों में विभाजित न किया जाए। इस लिहाज से प्रदेश में बने नए जिलों (जैसे सारंगढ़-बिलाईगढ़, मोहला-मानपुर, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर और सक्ती) की भौगोलिक सरहदें ही आगामी लोकसभा क्षेत्रों का नया नक्शा तय करने में सबसे निर्णायक भूमिका निभाएंगी।

मन की बात : 'युवाओं के सामने बड़ी चुनौती बनी ड्रग्स', पीएम मोदी बोले- इच्छाशक्ति से जीतें जंग



नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' का प्रसारण शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम के जरिए देशवासियों से जुड़ रहे हैं और विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार साझा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 'मन की बात, समाज के हर वर्ग, देश के हर हिस्से की उपलब्धियों को सामने लाने का मंच है और इसमें हम समाज के सामने मौजूद चुनौतियों की बात करते हैं, लोगों को जागरुक भी करते हैं 7 आज 'मन की बात' में, मैं सबसे पहले ऐसा ही एक विषय उठा रहा हूं और वो है 'ड्रग्स' यानी 'नशे की लत' । साथियो, आज दुनिया में भारत के युवाओं की प्रतिभा की कितनी चर्चा हो रही है। हमारे युवा बड़े-बड़े सपने देख रहे हैं, उन्हें पूरा करने के लिए जी-जान से जुटे हैं, लेकिन, युवाओं के इन सपनों के सामने ड्रग्स, नशा एक बड़ी चुनौती बन गई है। मुझे संतोष है कि आज देश में नशे के खिलाफसमाज की सक्रियता बढ़ रही है।'नशा मुक्त युवा अभियान' भी जोरों पर चल रहा है। ऐसे कितने ही प्रेरक उदाहरण हमारे सामने आ रहे हैं जहां युवाओं ने अपनी इच्छा शक्ति से नशे की लत को हराया है, कठिन से कठिन परिस्थियों से लड़ाई लड़ करके बाहर निकले हैं। वे खुद से लड़े हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा दी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'मन की बात' में सरकारी कर्मचारियों के सीखने के उत्साह की सराहना की। उन्होंने कहा कि जीवन में जब भी हम कुछ नया सीखते हैं, तो हमें एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है और सीखने की तो कोई उम्र भी नहीं होती। आज, मैं, आपसे देश के उन लाखों सरकारी कर्मचारियों की बात करना चाहता हूं, जिनमें कुछ नया सीखने का उत्साह देखने को मिल रहा है। इनमें से कई लोग 20-25 वर्षों से सरकारी सेवा में हैं। इतना लंबा अनुभव होने के बावजूद ये अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए कुछ नया सीखने के लिए भी समय निकाल रहे हैं, और इसके लिए वो, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म की मदद ले रहे हैं। इसका नाम है 'आईगॉट कर्मयोगी'। इस प्लेटफॉर्म पर सरकारी कर्मचारियों के लिए 17 भारतीय भाषाओं में 7 हजार से ज्यादा कोर्स उपलब्ध हैं। लाखों सरकारी कर्मचारियों ने अनेकों कोर्स पूरे किए हैं 7 कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई कर रहा है, तो कोई भारतीय सांकेतिक भाषा सीख रहा है। एआई और नई तकनीक की पढ़ाई को लेकर हमारे कर्मयोगियों में, मैं, विशेष उत्साह देख रहा हूं। इससे जुड़े 200 से ज्यादा कोर्स ऐसे हैं इनमें सवा-तीन करोड़ से ज्यादा कोर्स पूरा हो चुके हैं।

भारत ने रूस से घटाई तेल की खरीदः पश्चिम एशिया से बढ़ाया आयात, बढ़ गया माल ढुलाई का खर्च

नईदिल्ली। भारत ने नवंबर में रूस से कच्चे तेल की खरीद काफी घटा दी है। इस साल के मध्य में रूस से तेल का आयात सबसे ज्यादा था। लेकिन अब इसमें गिरावट आई है। इसकी कई वजहें हैं। पश्चिम एशिया से तेल की आपूर्ति में बदलाव हुआ है। रूस ने तेल पर मिलने वाली छूट कम कर दी है। माल ढुलाई का खर्च भी बढ़ गया है।

इन वजहों से भारतीय तेल रिफाइनर अब दूसरे देशों से भी तेल खरीद रहे हैं। हालांकि, भारत की तेल खरीद रणनीति में रूस की अहमियत अभी खत्म नहीं हुई है। रूस का तेल अब भी भारत के लिए एक अहम स्रोत बना हुआ है। केप्लर के आंकड़ों के मुताबिक, नवंबर में रूस से भारत का कच्चे तेल का आयात घटकर करीब 16.5 लाख बैरल प्रतिदिन रह गया। जुलाई में यह करीब 28 लाख बैरल प्रतिदिन के रिकॉर्ड स्तर पर था। केप्लर कमोडिटी बाजार से जुड़ी जानकारी देने वाली कंपनी है। इसके बाद सितंबर में आयात घटकर 18.7 लाख बैरल प्रतिदिन रह गया था। अक्तूबर में इसमें थोड़ी बढ़ोतरी हुई। यह 20.5 लाख बैरल प्रतिदिन पहुंच गया था।



जानिए भारत ने पश्चिम एशिया से क्यों बढ़ाई खरीद?

रूस से आयात में गिरावट के साथ ही पश्चिम एशिया के पुराने तेल आपूर्तिकर्ताओं से खरीद बढ़ी है। खासकर सऊदी अरब और इराक से तेल की आपूर्ति में सुधार हुआ है। होर्मुज जलडमरूमध्य से कच्चे तेल की आवाजाही धीरे-धीरे बेहतर हो रही है। नवंबर में भारत ने सऊदी अरब और इराक से कुल करीब 16.1 लाख बैरल प्रतिदिन तेल खरीदा। अक्तूबर में यह आंकड़ा करीब 10.3 लाख बैरल प्रतिदिन था। भारतीय रिफाइनर ने ब्राजील और वेनेजुएला से भी तेल की खरीद बढ़ाई है। इससे पता चलता है कि भारत अलग-अलग क्षेत्रों से तेल खरीदने पर जोर दे रहा है। केप्लर में तेल बाजार के विश्लेषण से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी सुमित रिटोलिया ने कहा, रूस अब भी भारत का सबसे बड़ा एकल कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता है। लेकिन इस साल के मध्य से उसकी हिस्सेदारी घट रही है। उन्होंने कहा, 'इसी समय हम पश्चिम एशिया के पुराने आपूर्तिकर्ताओं से खरीद में सुधार देख रहे हैं। खासकर सऊदी अरब और इराक से। होर्मुज जलडमरूमध्य से कच्चे तेल की आवाजाही धीरे-धीरे बेहतर हो रही है। इससे भारतीय रिफाइनरों को मध्य पूर्व से ज्यादा तेल खरीदने का मौका मिला है'।



संपादकीय

साफ-सुथरा खेल

लोकसभा सीटों का हड़बड़ी वाला परिसीमन

ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने साल 2029 में होने वाले अगले आम चुनाव के लिए, आनन-फानन में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन को अपनी रणनीति का केंद्रीय हिस्सा बनाना तय किया है। जैसी कि मौजूदा संवैधानिक व्यवस्था है, अभी चल रही 'जनगणना 2027' के आंकड़े जारी होते ही नये परिसीमन की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी। वह पूर्व-निर्धारित रास्ता, जो राज्यों में जनसंख्या वितरण पर आधारित है, उन राज्यों का प्रतिनिधित्व काफी घटा देगा जिन्होंने पिछले परिसीमन के बाद से अपनी जनसंख्या स्थिर कर ली है। केंद्र ने अब लोकसभा सीटों के अंतर-राज्यीय वितरण में बदलाव पर संवैधानिक रोक को 25 साल और बढ़ाकर साल 2051 तक करने, साथ ही सदन में कुल सीटों की संख्या बढ़ाकर अधिकतम 850 करने का प्रस्ताव रखा है। हर राज्य के भीतर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण साल 2011 की जनगणना के आधार पर किया जायेगा। परिसीमन की इस कवायद से महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण भी लागू होगा, जिसे संसद ने साल 2023 में मंजूरी दी थी। 'एक व्यक्ति, एक वोट' के सिद्धांत को संघवाद के सिद्धांतों – जो राज्यों के सामूहिक अधिकारों की हिफाजत से जुड़े हैं – के साथ संतुलित करने की जरूरत को ध्यान में रखते हुए, ये प्रस्ताव भारत के लिए आगे बढ़ने का एक वाजिब तरीका हैं। इसके बावजूद, लोकसभा सीटों का अंतर-राज्यीय वितरण लोकतंत्र और संघवाद का इतना केंद्रीय प्रश्न है कि कोई बदलाव करने से पहले कई स्तरों पर गंभीर विचार-विमर्श किया जाना चाहिए।

> **"केंद्र ने अब लोकसभा सीटों के अंतर-राज्यीय वितरण में बदलाव पर संवैधानिक रोक को 25 साल और बढ़ाकर साल 2051 तक करने, साथ ही सदन में कुल सीटों की संख्या बढ़ाकर अधिकतम 850 करने का प्रस्ताव रखा है। हर राज्य के भीतर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण साल 2011 की जनगणना के आधार पर किया जायेगा।**

यह दल-बदल और जोड़-तोड़ के जरिए संविधान संशोधन पारित कराने की कोशिश कर रहे केंद्र के तरीके को संदिग्ध और नेकनीयती से रहित बनाता है। अगर केंद्र साल 1971 की जनगणना के आधार पर अंतर-राज्यीय वितरण की संवैधानिक गारंटी आगे बढ़ाने को तैयार होता, तो वह इस मुद्दे पर सर्वदलीय सहमति बना सकता था। इसके बजाय, अप्रैल में, उसने सीटों का मौजूदा अनुपात बनाये रखने का वादा करके एक फरेबी चाल चली, जबकि उसके द्वारा पेश संविधान संशोधन उस वादे को असंवैधानिक बना देता। अभी जब केंद्र सरकार सहयोगपूर्ण दिखना चाहती है, भारत के संघीय लोकतंत्र में इस तरह के दूरगामी प्रभाव वाले कदम को आगे बढ़ाने का ज्यादा मुनासिब तरीका यह होगा कि इन विधेयकों को एक संसदीय समिति के पास भेजा जाए, जो इनका विस्तार से परीक्षण कर सके और एक राष्ट्रीय संवाद का सृजन कर सके। ज्यादा बड़ी लोकसभा अपनी तरह की चुनौतियां पैदा करेगी, लेकिन इसके आकार को बढ़ाने का तर्क पूर्णतया बेबुनियाद नहीं है क्योंकि साल 1973 में पिछले परिसीमन का आधार बनी साल 1971 की जनगणना के बाद से भारत की आबादी कम से कम 2.6 गुना बढ़ चुकी है। केंद्र को इस बेहद महत्वपूर्ण सवाल पर हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। यह किसी विधेयक को पारित कराने के लिए पर्याप्त वोट जुटाने भर का मामला नहीं है। यह आम सहमति पर आधारित होना चाहिए, जैसा कि साल 1976 में और फिर 2001 में, क्रमशः कांग्रेस और भाजपा के प्रधानमंत्री के अधीन हुआ था।

भारत में बाल पोषण को मजबूत बनाना

एनीमिया से व्यापक रूप से निपटने के लिए संपदा से मिली अंतर्दृष्टि



प्रो. नरेंद्र अरोरा



आईसीएमआर-एनआईएन द्वारा 2023-25 के दौरान किया गया सर्वे फॉर असेसमेंट ऑफ मार्कर्स ऑफ पॉपुलेशन हेल्थ, एक्टिविटी, डाइट एंड एंथ्रोपोमेट्री (संपदा), भारत की पोषण संबंधी चुनौतियों को और अधिक व्यापक रूप से समझने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। संपदा केवल एनीमिया से पीड़ित बच्चों की गिनती करने से आगे बढ़ते हुए, एनीमिया के लिए जिम्मेदार पोषण संबंधी और अन्य कारकों की जांच करने का भी एक बेहतरीन मौका देता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि बचपन में होने वाले एनीमिया के परिणाम शारीरिक गतिविधि, मानसिक विकास, ध्यान लगाने की क्षमता, सीखने की प्रक्रिया और भविष्य की मानव पूंजी तक पर असर डाल सकते हैं।

पिछले राष्ट्रीय सर्वेक्षणों के विपरीत, जिनमें हीमोग्लोबिन मापने के लिए उंगली से लिए गए रक्त का उपयोग किया जाता था, संपदा में नसों से लिए गए रक्त का उपयोग किया गया है। डब्ल्यूएचओ के 2024 के हीमोग्लोबिन कट-ऑफ का उपयोग करते हुए, यह एनीमिया और उससे जुड़े पोषण संबंधी कारकों का अधिक व्यापक आकलन प्रदान करता है। 12 से 59 महीने की उम्र के बच्चों में लगभग 42% बच्चे एनीमिया से पीड़ित पाए गए। ये आंकड़े एनएफएचएस-5 में इसी आयु वर्ग (12-59 महीने) के बच्चों में बताए गए 64% एनीमिया के प्रसार की तुलना में काफी कम हैं। यह कम दर बेहतर तरीकों के इस्तेमाल और एनीमिया में वास्तविक कमी, दोनों का नतीजा हो सकती है। इसलिए, समय के साथ आए वास्तविक बदलावों को समझने के लिए भविष्य में ऐसे सर्वेक्षणों की ज़रुरत होगी, जिनकी तुलना की जा सके। हालाँकि, एनीमिया का मतलब केवल आयरन की कमी नहीं है। 12 से 59 महीने के लगभग 23% बच्चों और 5 से 9 साल के 17.6% बच्चों में आयरन की कमी पाई गई। वहीं, 16.4% और 6.3% बच्चों में एनीमिया के साथ-साथ आयरन की कमी भी देखी गई। गौरतलब है कि मध्यम या गंभीर एनीमिया वाले छोटे बच्चों में से 65.7% बच्चों में आयरन की कमी थी। ये निष्कर्ष बताते हैं कि आयरन सप्लीमेंट देना कितना ज़रुरी है, खासकर छोटे बच्चों के लिए। हालाँकि, ये यह भी दर्शाते हैं कि एनीमिया के एक बड़े हिस्से का कारण केवल आयरन की कमी नहीं है। संक्रमण, सूजन, परजीवी बीमारियाँ, अन्य पोषक तत्वों की कमी और जन्मजात हीमोग्लोबिन विकार भी इस समस्या का कारण हो सकते हैं। इसलिए, यदि एनीमिया बना रहता है या आयरन के इलाज से कोई सुधार नहीं दिखता है, तो बार-बार आयरन की खुराक देने के बजाय, डॉक्टर से विस्तृत चिकित्सीय जाँच करानी चाहिए। भारतीय बच्चों, किशोरों और महिलाओं में एनीमिया का लगातार बना रहना यह बताता है कि बेहतर आहार सहित व्यापक उपायों की आवश्यकता है।

सर्वेक्षण में यह भी पाया गया कि छोटे बच्चों में लगभग 37% और स्कूली उम्र के बच्चों में 46% बच्चों में विटामिन B12 की कमी है। दोनों आयु समूहों में लगभग 10% बच्चों में फोलेट की कमी देखी गई। दिलचस्प बात यह है कि एनीमिया से पीड़ित और एनीमिया से मुक्त, दोनों तरह के बच्चों में विटामिन B12 और फोलेट की कमी का स्तर लगभग एक जैसा था। इससे पता चलता है कि सर्वेक्षण में शामिल लोगों के बीच, एनीमिया के मुख्य कारण के रूप में इन कमियों की भूमिका शायद उतनी बड़ी नहीं है, हालांकि स्वास्थ्य पर इनके व्यापक प्रभाव अभी भी महत्वपूर्ण हैं। इन नतीजों से यह स्पष्ट होता है कि एनीमिया के हर मामले को केवल आयरन की कमी से जोड़कर देखने के बजाय, हमें बेहतर खान-पान के जरिए सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करने पर ध्यान देना चाहिए।

भारत की खाद्य वितरण प्रणाली दुनिया के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों में से एक है। इसने आर्थिक रूप से कमजोर लाखों परिवारों तक अनाज पहुँचाने में अहम भूमिका निभाई है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) और खाद्य सुरक्षा से जुड़े अन्य उपायों के जरिए, लोगों को मुख्य अनाज उपलब्ध हो पाया है, जिससे वे भुखमरी और खाद्य असुरक्षा से बच सके हैं। साथ ही, इससे परिवारों के पोषण के लिए एक मजबूत आधार भी मिला है। कुछ प्रमाण यह भी बताते हैं कि इन कार्यक्रमों से पोषण के स्तर पर और भी व्यापक लाभ मिल सकते हैं।

2025 में अमेरिकन इकोनॉमिक जर्नल: एप्लाइड इकोनॉमिक्स में प्रकाशित एक शोध से पता चला है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम ने अध्ययन किए गए राज्यों में परिवारों के खान-पान में विविधता बढ़ाई है और बच्चों में उम्र के हिसाब से कम लंबाई की समस्या को कम किया है। यह पोषण संबंधी परिणामों में खाद्य-आधारित सामाजिक सुरक्षा के योगदान को पुष्ट करता है।

आगे चलकर, खाद्य सुरक्षा और पोषण कार्यक्रमों के बीच बेहतर तालमेल बिठाकर इस मजबूत आधार को और मजबूत करने का अवसर है। मुख्य खाद्य पदार्थों के साथ-साथ विविध प्रकार के भोजन तक पहुंच होने से, शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाने में मदद मिल सकती है।

पोषण की दृष्टि से पर्याप्त आहार के लिए विभिन्न खाद्य समूहों का संयोजन आवश्यक है: प्रोटीन, आयरन और फोलेट के लिए दालें और फलियां, फोलेट और अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां, पौधों से मिलने वाले आयरन के अवशोषण को बेहतर बनाने के लिए विटामिन-सी से भरपूर फल और सब्जियां, विटामिन-बी12 और अन्य जरूरी पोषक तत्वों के लिए अंडे, दूध, मछली और मांस (जहां इनका सेवन स्वीकार्य और किफायती हो) और खान-पान में विविधता लाने के लिए मोटे अनाज तथा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध अन्य पौष्टिक खाद्य पदार्थ। इसी तरह, जीवन के शुरुआती महत्वपूर्ण दो वर्षों के दौरान, आंगनवाड़ी सेवाओं को बच्चों के लिए पूरक आहार देने की प्रथाओं को और मजबूत करना चाहिए।

आईसीएमआर के सम्पदा से सामने आए साक्ष्य भारत को अपने खाद्य और पोषण कार्यक्रमों को और मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर देते हैं। खाद्य सुरक्षा पहलों की सफलताओं को आधार बनाते हुए, अब पोषण सुरक्षा पर अधिक ध्यान दिया जा सकता है। इसमें आहार में विविधता, सूक्ष्म पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा और एनीमिया की प्रभावी रोकथाम तथा प्रबंधन पर खास जोर दिया जा सकता है। आखिरकार इसका लक्ष्य केवल भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करना ही नहीं, बल्कि हर बच्चे के लिए बेहतर पोषण और एक स्वस्थ भविष्य सुनिश्चित करना है।

लेखक, द इंकलेन ट्रस्ट इंटरनेशनल के मुख्य वैज्ञानिक और मेंटर हैं तथा एम्स बिलासपुर के अध्यक्ष हैं।

राष्ट्रीय पहचान की ओर भखारा का आमा तालाब

डॉ. ओम डहरिया

प्रकृति अपनी गोद में अनगिनत धरोहरों को संजोए रखती है। कहीं नदियों की कलकल ध्वनि जीवन का संगीत रचती है, तो कहीं तालाब और झीलें जैव विविधता के अनमोल संसार को अपने भीतर समेटे रहती हैं। ये जलस्रोत केवल पानी के भंडार नहीं, बल्कि असंख्य जीव-जंतुओं, वनस्पतियों और पक्षियों के जीवन का आधार होते हैं। इनके किनारों पर पनपता प्राकृतिक संसार मानव और प्रकृति के बीच सदियों पुराने रिश्ते की कहानी कहता है। ऐसी ही एक प्राकृतिक धरोहर है धमतरी जिले के भखारा का आमा तालाब, जो अब अपनी स्थानीय पहचान से आगे बढ़कर राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने की दिशा में अग्रसर है। विधायक एवं पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर की पहल और जिला प्रशासन के सहयोग से आमा तालाब को रामसर साइट के रूप में विकसित एवं नामांकित करने के प्रयास तेज हुए हैं। यह पहल केवल एक तालाब के विकास की परिकल्पना नहीं, बल्कि प्रकृति की विरासत को सुरक्षित रखने और आने वाली पीढ़ियों को समृद्ध पर्यावरण सौंपने का दूरदर्शी प्रयास है।

इस दिशा में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (बीएसआई), प्रयागराज तथा छत्तीसगढ़ वेटलैंड प्राधिकरण के विशेषज्ञों की टीम ने आमा तालाब का निरीक्षण कर इसकी पर्यावरणीय और जैविक संभावनाओं का आकलन किया। विशेषज्ञों ने तालाब की प्राकृतिक संरचना, जैव विविधता, जलीय पारिस्थितिकी, प्रवासी पक्षियों के आगमन तथा उनके अनुकूल पर्यावास की संभावनाओं का बारीकी से अध्ययन किया। इस निरीक्षण के आधार पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इसके बाद संरक्षण एवं विकास संबंधी प्रस्ताव राज्य सरकार के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

आमा तालाब की विशेषता केवल इसका जल विस्तार नहीं, बल्कि इससे जुड़ी प्राकृतिक संभावनाएं हैं। यदि यहां जैव विविधता के अनुकूल वातावरण को संरक्षित और विकसित किया जाता है, तो यह प्रवासी पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण आश्रय स्थल बन सकता है। दूर देशों और प्रदेशों से आने वाले पक्षियों का कलरव, जल में पनपता जलीय जीवन और आसपास की हरियाली इस क्षेत्र को प्रकृति प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना सकती है। इस प्रकार आमा तालाब पर्यावरण संरक्षण के साथ प्रकृति आधारित पर्यटन और स्थानीय आजीविका के नए अवसरों का माध्यम भी बन सकता है।

विधायक अजय चंद्राकर की इस पहल का महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि उन्होंने क्षेत्र की प्राकृतिक संपदा में छिपी संभावनाओं को पहचानकर उसे व्यापक पहचान दिलाने का प्रयास किया है। स्थानीय स्तर पर मौजूद प्राकृतिक धरोहरों को वैज्ञानिक संरक्षण और योजनाबद्ध विकास से राष्ट्रीय महत्व के स्थलों के रूप में स्थापित किया जा सकता है। आमा तालाब को रामसर साइट के रूप में विकसित करने की पहल इसी सोच का परिणाम है। यह क्षेत्र के लोगों के लिए गौरव का विषय होने के साथ-साथ पर्यावरण के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी का संदेश भी है।



छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संपदा और जैव विविधता के मामले में समृद्ध प्रदेश है। यहां के वन, नदियां, जलाशय और आर्द्रभूमियां प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आर्द्रभूमियां भूजल पुनर्भरण, जल संरक्षण, बाढ़ के प्रभाव को कम करने, जलीय जीवों और पक्षियों को आश्रय देने तथा स्थानीय पारिस्थितिकी को संतुलित रखने में अहम योगदान देती हैं। इसलिए इनका संरक्षण केवल पर्यावरण का विषय नहीं, बल्कि मानव जीवन और भविष्य की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है।

आर्द्रभूमि संरक्षण के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। प्रदेश का कोपरा जलाशय राज्य का पहला रामसर स्थल घोषित हो चुका है। यह उपलब्धि प्रदेश की प्राकृतिक विरासत और उसके संरक्षण के प्रति बढ़ती प्रतिबद्धता का प्रमाण है। आर्द्रभूमियों के संरक्षण को जनभागीदारी से जोड़ने के लिए प्रदेश में 500 से अधिक वेटलैंड मित्र तैयार किए गए हैं। वहीं, 2.25 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाले 11,098 वेटलैंड का ग्राउंड ट्रुथिंग एवं सीमा निर्धारण कर छत्तीसगढ़ ने इस कार्य में देश में अग्रणी स्थान हासिल किया है। जैव विविधता और वेटलैंड संरक्षण को लेकर विधायकों के लिए नवा रायपुर स्थित वन मुख्यालय में कार्यशाला भी आयोजित की जा चुकी है। इसके माध्यम से आर्द्रभूमियों के महत्व, उनके संरक्षण और विकास में जनप्रतिनिधियों की भूमिका को रेखांकित किया गया है। प्रदेश सरकार ने छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 के तहत वर्ष 2030 तक प्रदेश की 20 आर्द्रभूमियों को रामसर स्थल के रूप में नामांकित कराने का लक्ष्य रखा है। कोपरा जलाशय के बाद छिंदारी, पैलीमेटा और नीमगांव जलाशय सहित अन्य संभावित स्थलों को भी इस दिशा में विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

इसी व्यापक लक्ष्य की कड़ी में भखारा का आमा तालाब भी अपनी नई पहचान की ओर बढ़ रहा है। रामसर स्थल के रूप में नामांकन की दिशा में विशेषज्ञों का निरीक्षण इस यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव है। यह पहल बताती है कि प्रकृति के संरक्षण की शुरुआत अपने आसपास की धरोहरों को पहचानने और उन्हें सहेजने से होती है। किसी तालाब को बचाना केवल उसके पानी को बचाना नहीं, बल्कि उससे जुड़े पक्षियों, वनस्पतियों, जलीय जीवों और पूरे प्राकृतिक तंत्र को सुरक्षित रखना है।

विधायक अजय चंद्राकर ने आमा तालाब के संरक्षण और इसे रामसर साइट के रूप में विकसित करने की पहल को क्षेत्र के लिए गौरव का विषय बताया है। उनका कहना है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और विकास के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियों को समृद्ध जैव विविधता और बेहतर पर्यावरण का लाभ मिल सके।

आज जब दुनिया जलवायु परिवर्तन, घटते प्राकृतिक संसाधनों और जैव विविधता के संकट जैसी चुनौतियों से जूझ रही है, तब स्थानीय स्तर पर आर्द्रभूमियों का संरक्षण और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। भखारा के आमा तालाब को राष्ट्रीय पहचान दिलाने की यह पहल इसी व्यापक पर्यावरणीय सोच से जुड़ी है। यह आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति की अमूल्य पूंजी बचाने का प्रयास है।

यदि आमा तालाब रामसर स्थल के रूप में नामांकित होता है, तो यह केवल भखारा या धमतरी जिले की उपलब्धि नहीं होगी, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का नया अध्याय होगा। विधायक अजय चंद्राकर की पहल से शुरू हुई यह कोशिश स्थानीय विरासत को राष्ट्रीय पहचान दिलाने के साथ प्रकृति के प्रति संवेदनशील और जिम्मेदार समाज के निर्माण की दिशा में भी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।

सहायक जनसंपर्क अधिकारी

संसार के सुख-दुःख को सहने के लिए भीतर की यात्रा करें

पं. विजयशंकर मेहता

दुनियादारी के सारे काम बाहर की यात्राएं हैं और तकनीक उनमें मददगार है। लेकिन जब हम संसार में होते हैं, तब संसार के दुःख में भी होते हैं। जिस वस्तु से आज सुख मिल रहा है, कल वही दुःख देगी। संसार से मिले सुख-दुःख को सहने के लिए एक यात्रा भीतर की तरफ करनी पड़ती है। कई प्रयोग साधु-संतों ने बताए हैं। भीतर जाने का एक प्रयोग है- हाथ से पत्र लिखना। इस अभ्यास को कभी न छोड़ें। लेख लिखना और कोई अन्य लेखन करना अलग बात है। पर जब आप किसी को पत्र लिखते हैं तो अपने आप में डूबते हैं और पत्र में जो अभिव्यक्त होता है, वह बिल्कुल आपकी आत्मा होती है। प्रियजनों को पत्र लिखना बंद ना करें। हाथ से ना लिख सकें तो तकनीक के माध्यम से लिखें, लेकिन पत्र लिखिए। और पत्र लिखते समय अपने आप को अत्यधिक ईमानदार बनाए रखें। महान लोगों के पत्र पढ़िए। भाषण देते समय वह व्यक्ति अलग था, लेकिन पत्र लिखते समय वह व्यक्ति कोई और होता है। क्यों ना यह प्रयोग हम भी करें?

धुएं से आजादी और महिला सशक्तिकरण की नई उड़ान

धनंजय राठौर

लकड़ी, कोयले और कंडों के पारंपरिक चूल्हों के बजाय एलपीजी मिलने से रसोई धुएं से मुक्त मिली, जिससे महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य व सांस संबंधी दिक्कतों में सुधार हुआ है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ में लगभग 39 लाख 73 हजार से अधिक महिलाओं को एलपीजी गैस कनेक्शन देकर चूल्हे के धुएं से राहत दिलाई है।

छत्तीसगढ़ में 39 लाख से अधिक महिलाओं को चूल्हे के धुएं से मिली आजादी

छत्तीसगढ़ के ग्रामीण और वनांचल क्षेत्रों की लाखों महिलाओं के जीवन में एक ऐतिहासिक बदलाव आया है। वर्षों तक मिट्टी के चूल्हे पर लकड़ी और उपलों के धुएं के बीच खाना पकाने की मजबूरी से जूझ रही महिलाओं को अब स्वच्छ ईंधन मिल रहा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से प्रदेश की 39 लाख से अधिक महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी (रसोई गैस) कनेक्शन प्राप्त हुए हैं, जिससे उन्हें न केवल धुएं से मुक्ति मिली है, बल्कि उनके स्वास्थ्य, समय और सम्मान की भी रक्षा हुई है।

एक बड़ी सामाजिक और स्वास्थ्य क्रांति

पारंपरिक चूल्हे से निकलने वाला जहरीला धुआं ग्रामीण महिलाओं के लिए साइलेंट किलर की तरह था। एक दिन में घंटों चूल्हे के सामने बैठना सैकड़ों सिगरेट पीने के बराबर नुकसानदायक माना जाता है, जिससे श्वसन संबंधी रोग, आंखों में जलन और फेफड़ों की गंभीर बीमारियां होती थीं। उज्ज्वला योजना ने सीधे तौर पर इस समस्या पर प्रहार किया है। आज बस्तर के सुदूर वनांचल से लेकर सरगुजा की पहाड़ियों और मैदानी गांवों तक, रसोईघरों में धुएं के गुबार की जगह नीली लौ ने ले ली है।

समय की बचत और आत्मनिर्भरता की ओर कदम

पहले ग्रामीण महिलाओं का एक बड़ा हिस्सा जंगल से जलाऊ लकड़ी बीनने, उपले थापने और फिर चूल्हा जलाने में ही बीत जाता था। इस कठिन श्रम के कारण वे न तो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दे पाती थीं और न ही किसी आर्थिक गतिविधि से जुड़ पाती थीं। गैस कनेक्शन मिलने से खाना बनाना बेहद आसान और तेज हो गया है। इस बचे हुए समय का उपयोग अब महिलाएं स्व-सहायता समूहों से जुड़कर रोजगार करने, बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देने और परिवार की आय बढ़ाने में कर रही हैं। ग्रामीण और वंचित वर्ग की महिलाओं को पहली बार में एलपीजी कनेक्शन, गैस चूल्हा और पहला रिफिल पूरी तरह निःशुल्क प्रदान किया जाता है।

पर्यावरण संरक्षण में भी अहम योगदान

उज्ज्वला योजना का लाभ केवल रसोई की चारदीवारी तक सीमित नहीं है। छत्तीसगढ़ एक वन-बहुल राज्य है। 39 लाख 73 हजार से अधिक परिवारों के एलपीजी अपनाने से जलाऊ लकड़ी के लिए पेड़ों की कटाई में भारी कमी आई है। यह योजना पर्यावरण संतुलन बनाए रखने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने में भी एक मील का पत्थर साबित हो रही है। बिलासपुर जिले में 2 लाख 94 हजार 134 महिलाओं को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से एलपीजी गैस कनेक्शन देकर चूल्हे के धुएं से राहत दिलाई है। इसी प्रकार जांजगीर-चांपा जिले में



2,74,650, रायगढ जिले में 2,30,101, बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में 2,27,132, महासमुंद जिले में 1,93,464, कोरबा जिले में 1,55,683, जशपुर जिले में 1,42,185 , बस्तर जिले में 1,33,555, बेमेतरा जिले में 1,33,377, धमतरी जिले में 1,28,643, कवर्धा (कबीरधाम) जिले में 1,20,895, मुंगेली जिले में 1,19,549 महिलाओं को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से एलपीजी गैस कनेक्शन देकर चूल्हे के धुएं से राहत दिलाई है।

जशपुर जिले के विकासखंड बगीचा विकासखंड बगीचा निवासी क्रांति यादव ने गैस सिलेंडर प्राप्त कर प्रसन्नता जताई। उन्होंने कहा कि अब उन्हें पारंपरिक चूल्हे के धुएँ से छुटकारा मिलेगा। पहले रसोई में धुएँ के कारण आँखों में जलन और सांस लेने में परेशानी होती थी, लेकिन अब गैस कनेक्शन मिलने से वे स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण में आसानी से भोजन बना सकेंगी। इसी प्रकार ग्राम मड़िया निवासी फूलमती नगेसिया ने बताया कि वे अब तक लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाती थीं। धुएँ के कारण घर का वातावरण खराब हो जाता था और उन्हें काफी असुविधा होती थी। निःशुल्क गैस कनेक्शन मिलने से अब खाना जल्दी और साफ-सुथरे तरीके से बन सकेगा। उन्होंने कहा कि यह योजना उनके लिए बहुत राहत लेकर आई है।

सिलेंडर मिलते ही महिलाओं के चेहरों पर सुकून और खुशी साफ झलक उठी

राजनांदगांव जिले के मेड़ेसरा निवासी राजेश्वरी साहू ने बताया कि निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन मिलने से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाओं को सुरक्षित, स्वच्छ और किफायती ईंधन सुलभ हुआ है। रवेली निवासी परमेश्वरी वर्मा ने कहा कि पहले चूल्हे के धुएं से छोटे बच्चों को भी परेशानी होती थी। अब गैस सिलेंडर मिलने से बच्चों को धुएं से राहत मिलेगी और भोजन जल्दी व सुरक्षित तरीके से बन सकेगा। सिलेंडर मिलते ही महिलाओं के चेहरों पर सुकून और खुशी साफ झलक उठी। यह खुशी केवल सुविधा मिलने की नहीं, बल्कि वर्षों से झेली जा रही कठिनाइयों से मुक्ति की थी। कच्चे मकानों में जीवन यापन कर रहीं राजेश्वरी साहू, मीना यादव, परमेश्वरी वर्मा और पावर्ती के लिए यह दिन सपने के साकार होने जैसा रहा।

महिलाओं के नाम पर गैस कनेक्शन जारी होने से परिवार में उनकी निर्णय लेने की क्षमता और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ी है। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी और रिफिल की सुगम उपलब्धता ने इस योजना को जमीनी स्तर पर सफल बनाया है। आज छत्तीसगढ़ की ये 39 लाख 73 से अधिक महिलाएं केवल एक योजना की लाभार्थी नहीं हैं, बल्कि वे स्वस्थ परिवार, स्वच्छ पर्यावरण और सशक्त समाज की संवाहक बन चुकी हैं। धुएं से मिली यह आजादी छत्तीसगढ़ के ग्रामीण विकास की एक सुनहरी इबारत लिख रही है।

संयुक्त संचालक, जनसंपर्क

ITR फाइल 500/-
Whatsapp पर बनवाएँ
Income Tax फाइल, GST रजिस्ट्रेशन, TDS रिफंड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट
CMA DATA, MSME, BALANCE SHEET, फूड लाइसेंस
हमारे Tax Expert आपकी मदद हेतु तैयार है।
www.onlytds.com
सम्पर्क - शेखर गुप्ता 9300755544 - 8878655544

श्रीकंचनपथ
भिलाई-दुर्ग

प्रिंट और डीजिटल मीडिया में
सभी प्रकार के विज्ञापन
के लिए
संपर्क करे
Mob.-:
9303289950
7987166110

प्रमुख खबरें

सामान्य ट्राईसाइकिल बनी शिव प्रसाद कुर्रे के लिए आत्मनिर्भरता की नई राह

भिलाई। शासन की जनकल्याणकारी योजनाएं जरूरतमंदों के जीवन में किस तरह नई उम्मीद और खुशियां लेकर आती हैं, इसका एक प्रेरणादायक उदाहरण रिसाली निवासी शिव प्रसाद कुर्रे हैं। शारीरिक बाध्यता के कारण उनके लिए स्वयं चलकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच पाना बेहद कठिन था। बिना ट्राईसाइकिल के उनका कहीं आना-जाना लगभग असंभव था। दैनिक जीवन के छोटे-छोटे कार्यों के लिए भी उन्हें दूसरों की सहायता का इंतजार करना पड़ता था। इस परेशानी से निजात पाने और आत्मनिर्भर बनने की उम्मीद के साथ श्री शिव प्रसाद कुर्रे ने समाज कल्याण विभाग में ट्राईसाइकिल प्रदान करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया।

सेवा सेतु प्रबंधकों को दिया गया प्रशिक्षण

दुर्ग। जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में सेवा सेतु के माध्यम से नागरिकों को प्रदान की जा रही शासकीय सेवाओं की प्रक्रिया को अधिक सरल, पारदर्शी एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से साइंस कॉलेज स्थित राधाकृष्णन हॉल में सेवा सेतु प्रबंधकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। उक्त प्रशिक्षण में जिले के सेवा सेतु प्रबंधकों को विभिन्न महत्वपूर्ण शासकीय सेवाओं की आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेजों, ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन प्रविष्टि एवं निराकरण की कार्यप्रणाली के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। प्रशिक्षण के दौरान गजट प्रकाशन, अनक्लीन बिजनेस सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, केंद्रीय ओबीसी एवं एससी/एसटी प्रमाण पत्र, स्थानांतरण प्रमाण पत्र सेवाओं की जानकारी दी गई।

बीएसपी ठेका श्रमिकों के लिए होगी 'श्रम स्पर्धा-2026' एथलेटिक्स मीट

भिलाई। भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा पहली बार संयंत्र में कार्यरत ठेका श्रमिकों के लिए विशेष रूप से 'श्रम स्पर्धा-2026' एथलेटिक्स मीट का आयोजन किया जा रहा है। मानव संसाधन विभाग के क्रीड़ा, सांस्कृतिक एवं नागरिक सुविधाएं तथा औद्योगिक संबंध एवं ठेका श्रमिक प्रकोष्ठ के संयुक्त प्रयासों से आयोजित यह पहल ठेका श्रमिकों को खेल गतिविधियों से जोड़ने तथा उनमें खेल भावना, आपसी एकता, सहयोग एवं टीम भावना को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह आयोजन 04 दिसंबर 2026 को आयोजित किया जाएगा। 'खेलेंगे साथ, बढ़ेंगे साथ - एकता और उत्साह के साथ' की थीम पर आयोजित यह एथलेटिक्स मीट प्रातः 6:00 बजे से 11:00 बजे तक सेल एथलेटिक्स ग्राउंड, सेक्टर-4 (बोकारो हॉस्टल) में होगी। इसमें महिला एवं पुरुष प्रतिभागियों के लिए 100 मीटर, 200 मीटर एवं 400 मीटर दौड़, गोला फेंक तथा रस्साकशी जैसी विभिन्न खेल स्पर्धाएं आयोजित की जाएंगी। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रत्येक पंजीकृत प्रतिभागी को निःशुल्क टी-शर्ट एवं कैप प्रदान की जाएगी। सभी प्रतिभागियों को सहभागिता प्रमाण-पत्र भी दिया जाएगा।

छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय के फेकल्टीज के लिए आवास निर्माण शुरू

■ **28.07 करोड़ की लागत, वर्कशॉप व छात्रावास भवन भी बनेगा**

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, नेवई में आधारभूत संरचना के विस्तार के क्रम में राज्य शासन द्वारा कुल 28.07 करोड़ की लागत के पांच निर्माण कार्यों को प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। लोक निर्माण विभाग के कार्यापालन अभियंता एके भट्टाचार्य ने बताया कि इन कार्यों में कुलपति निवास (बी-टाइप) 1, कुल सचिव, कुलाधिसचिव, प्राध्यापक एवं सह-प्राध्यापक निवास (डी-टाइप) 13, सहायक प्राध्यापक निवास (ई-टाइप) 10, वर्कशॉप भवन तथा 250 सीटर बालक छात्रावास का निर्माण शामिल है। उक्त सभी निर्माण कार्यों के कार्यादेश भी जारी कर दिए गए हैं।



छात्रावास का निर्माण पूर्ण होने पर संस्था में अध्ययनरत विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय परिसर में ही आवास की सुविधा मिलेगी, जिससे देश के अन्य राज्यों से आने वाले विद्यार्थी अपनी तकनीकी शिक्षा पर बेहतर ढंग से ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। कुलपति, अधिकारियों एवं शिक्षकों के लिए कुल 24 आवासों के निर्माण से शैक्षणिक वातावरण सुदृढ़ होगा, वहीं वर्कशॉप भवन के निर्माण से तकनीकी शिक्षा में प्रायोगिक प्रशिक्षण को बल मिलेगा। साथ ही, निर्माण गतिविधियों से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण विभाग मंत्री अरुण साव के मार्गदर्शन में लोक निर्माण विभाग द्वारा इन कार्यों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। राज्य शासन का उद्देश्य प्रदेश के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराना है, ताकि युवाओं को अपने ही प्रदेश में बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिल सके।

दुर्ग-भिलाई के सभी थानों व चौकियों में लगाए गए क्यूआर कोड

अब एक क्लिक पर मिलेगी ई-चालान की जानकारी, भुगतान भी होगा आसान

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। आम नागरिकों की सुविधा के लिए दुर्ग जिले के समस्त थाना-चौकियों एवं पुलिस कार्यालयों में ई-चालान भुगतान हेतु क्यूआर कोड स्टिकर लगाए गए। वाहन चालक अपने नजदीकी थाना-चौकी पहुंचकर क्यूआर कोड स्कैन करते हुए अपने वाहन का लंबित ई-चालान देख सकेंगे तथा ऑनलाइन भुगतान कर सकेंगे। क्यूआर कोड स्टिकर पर चित्रों एवं विवरण के माध्यम से ई-चालान देखने और भुगतान करने की प्रक्रिया 10 आसान चरणों में समझाई गई है।

आम नागरिकों को ई-चालान की जानकारी प्राप्त करने एवं उसका भुगतान करने में होने वाली असुविधा को दूर करने तथा ऑनलाइन भुगतान के दौरान साइबर ठगी से बचाने के उद्देश्य से पुलिस उप महानिरीक्षक व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल के निर्देशन में यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा जिले के समस्त थाना-चौकियों एवं पुलिस कार्यालयों में



ई-चालान भुगतान संबंधी क्यूआर कोड स्टिकर लगाए गए हैं। अब ई-चालान देखने और भुगतान करने के लिए इधर-उधर भटकने की आवश्यकता नहीं। वाहन चालक अपने नजदीकी थाना अथवा चौकी पहुंचकर वहां लगाए गए क्यूआर कोड स्टिकर को अपने मोबाइल से स्कैन कर सीधे ई-चालान की आधिकारिक वेबसाइट पर पहुंच सकेंगे। इसके माध्यम से वे अपने वाहन का लंबित चालान देख सकेंगे तथा ऑनलाइन भुगतान भी कर सकेंगे।

पूरी प्रक्रिया 10 आसान तरीकों से प्रदर्शित

इस क्यूआर कोड से ई-चालान व भुगतान प्रक्रिया को 10 सरल चरणों में प्रदर्शित किया गया है। इसमें Google Camera व Google Lens से क्यूआर कोड स्कैन करने, आधिकारिक वेबसाइट खोलने, Pay Challan विकल्प चुनने, वाहन नंबर एवं कैप्चा दर्ज करने, चालान का विवरण देखने तथा यूपीआई सहित अन्य ऑनलाइन माध्यमों से भुगतान करने की जानकारी दी गई है। भुगतान पूर्ण होने के पश्चात रसीद डाउनलोड एवं प्रिंट करने की प्रक्रिया भी समझाई गई है। स्टिकर में क्यूआर कोड के साथ परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट का लिंक भी दिया गया है।

भुगतान के लिए करें अधिकारिक वेबसाइट का उपयोग

साइबर सुरक्षा के दृष्टिकोण से नागरिकों से अपील है कि ई-चालान भुगतान के लिए केवल आधिकारिक वेबसाइट का ही उपयोग करें। किसी अनजान व्यक्ति द्वारा भेजे गए लिंक पर क्लिक न करें और न ही किसी के साथ OTP, बैंकिंग संबंधी गोपनीय जानकारी अथवा UPI PIN साझा करें। यातायात पुलिस दुर्ग आम नागरिकों से अपील करती है कि वे अपने वाहनों के लंबित ई-चालान की नियमित जांच करें, निर्धारित जुर्माने का समय पर भुगतान करें तथा यातायात नियमों का पालन कर सुरक्षित एवं जिम्मेदार वाहन चालक बनें।

रिसाली निगम क्षेत्र में वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट का कार्य शीघ्र होगा प्रारम्भ



■ **कलेक्टर ने किया स्थल निरीक्षण**

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। जिले के नगर निगम रिसाली छेत्र में वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट हेतु 134 करोड़ राशि की घोषणा मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा विगत दिवस रिसाली के वार्ड 18 में आयोजित कार्यक्रम में की गई है। मुख्यमंत्री के घोषणा को अमल में लाने प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर और कलेक्टर अभिजीत सिंह ने नगर निगम रिसाली, जल संसाधन और पीएचई के अधिकारियों के साथ आज चिन्हांकित स्थल का निरीक्षण किये।

उन्होंने अधिकारियों को अलग-अलग कम्पोनेंट वार एस्टीमेट बनाने के साथ नगर की भविष्य को ध्यान में रखते हुए योजना बनाने के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि नगर निगम रिसाली अपने प्रस्तावित कार्ययोजना के तहत नेवई उमरपोटी सीमा में स्थित डेम से पानी लेकर प्लांट स्थापित करेगा। आगामी 30 वर्ष को लेकर योजना तैयार की गई है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता 30 एमएलडी की होगी, लागत राशि 134 करोड़ है। प्लांट हेतु 5 एकड़ जमीन स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। योजना अंतर्गत 4 ओवर हेड टैंक प्रस्तावित है, जो 15वें वित्त से स्वीकृत है। डेम का केनाल संधारण कार्य हेतु 4 करोड़ स्वीकृत है। प्लांट से 26831 नलों को पानी दिया जाएगा।

भिलाई इस्पात संयंत्र में लार्ज ग्रुप इंटरेक्शन के माध्यम से सुरक्षा पर व्यापक संवाद

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। सेल-भिलाई इस्पात संयंत्र में सुरक्षा संस्कृति को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से प्रत्येक शनिवार आयोजित किए जा रहे लार्ज ग्रुप इंटरेक्शन की कड़ी में 8वें एलजीआई का आयोजन 28 नवम्बर 2026 को मानव संसाधन-ज्ञानार्जन एवं विकास केंद्र में किया गया। इस अवसर पर संयंत्र के निदेशक प्रभारी श्री चित्त रंजन महापात्र व कार्यपालक निदेशक (वर्क्स) राकेश कुमार ने अधिकारियों, कार्मिकों, पर्यवेक्षकों, ठेका श्रमिकों एवं सेफ्टी वॉरियर्स के साथ सीधा संवाद किया तथा कार्यस्थल पर सुरक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया।

कार्यक्रम में मुख्य महाप्रबंधक पुष्पा एम्ब्रोस, मुख्य महाप्रबंधक प्रशांत ओझा तथा महाप्रबंधक प्रभारी एसके श्रीवास्तव सहित संयंत्र के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

कार्यक्रम का उद्देश्य 'मेरा क्षेत्र, मेरी जिम्मेदारी' की भावना को प्रोत्साहित करना, सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करना तथा 'लाइन ऑफ फायर' से जुड़े संभावित खतरों के



प्रति जागरूकता बढ़ाना था। इस दौरान कार्यस्थल पर मोबाइल फोन के उपयोग से बचने, सीमित स्थानों में सुरक्षित तरीके से कार्य करने तथा एफआरटी हेलमेट के उपयोग को प्रोत्साहित करने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। 'लाइन ऑफ फायर' के अंतर्गत अनियंत्रित ऊर्जा मुक्त होने से उत्पन्न जोखिमपूर्ण स्थितियों तथा उनसे बचाव के उपायों पर चर्चा की गई। साथ ही, कार्यस्थल पर संभावित खतरों की पहचान कर जोखिमों का आकलन करने और निर्धारित सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन करते हुए आवश्यक सावधानियां बरतने के महत्व पर जोर दिया गया।

18.24 लाख रुपए की लागत से वार्ड 9 में सड़क का होगा डामरीकरण, महापौर अलका बाघमार ने किया शिलान्यास

■ **गोपाल मंदिर से चंद्राकर ट्रेडर्स बैगा पारा स्टेडियम तक बनेगी बेहतर सड़क**

श्रीकंचनपथ न्यूज

दुर्ग। नगर पालिक निगम दुर्ग। शहरवासियों को सुगम, सुरक्षित एवं बेहतर आवागमन सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नगर निगम द्वारा शहर की सड़कों के सुधार एवं अधोसंरचना विकास कार्यों को लगातार गति दी जा रही है। इसी क्रम में वार्ड क्रमांक 9 में 18.24 लाख रुपये की लागत से सड़क डामरीकरण कार्य कराया जाएगा। महापौर अलका बाघमार ने आज गोपाल मंदिर से चंद्राकर ट्रेडर्स, बैगा पारा स्टेडियम के समीप प्रस्तावित सड़क डामरीकरण कार्य का भूमिपूजन कर निर्माण कार्य की शुरुआत की।



भूमिपूजन के पश्चात महापौर अलका बाघमार ने सभापति श्याम शर्मा, लोक कर्म प्रभारी देव नारायण चन्द्राकर व निगम अधिकारियों के साथ निर्माण स्थल का निरीक्षण कर सड़क निर्माण कार्य की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्माण कार्य प्रारंभ करने से पहले स्थल को व्यवस्थित किया जाए तथा डामरीकरण कार्य निर्धारित मापदंडों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा किया जाए।

जर्जर सड़क से मिलेगी राहत

सड़क डामरीकरण कार्य पूर्ण होने के बाद वार्डवासियों को बेहतर सड़क की सुविधा मिलेगी। इस मार्ग से प्रतिदिन आवाजाही करने वाले हजारों लोगों को राहत मिलेगी। सड़क की खराब स्थिति के कारण होने वाली परेशानियों से निजात मिलने के साथ ही आवागमन अधिक सुगम, सुरक्षित एवं व्यवस्थित होगा। क्षेत्रवासियों को लंबे समय से बेहतर सड़क की आवश्यकता महसूस हो रही थी, जिसे देखते हुए नगर निगम द्वारा इस कार्य को प्राथमिकता से कराया जा रहा है। महापौर ने कहा कि सड़क निर्माण कार्य में गुणवत्ता एवं समय-सीमा का विशेष ध्यान रखा जाए। कार्य के दौरान नागरिकों को आवागमन में अनावश्यक परेशानी न हो।

गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं

उन्होंने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा और सभी कार्य निर्धारित समय में पूर्ण होने चाहिए। महापौर अलका बाघमार ने कहा कि नगर निगम दुर्ग शहर के सभी 60 वार्डों में नागरिकों की आवश्यकताओं के अनुरूप मूलभूत सुविधाओं एवं विकास कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा कर रहा है।

बाल अधिकारों, पॉक्सो अधिनियम, साइबर सुरक्षा एवं बाल संरक्षण पर हुआ व्यापक प्रशिक्षण

सुरक्षित बचपन अभियान के तहत दुर्ग में शिक्षकों को मिला विशेष प्रशिक्षण

श्रीकंचनपथ न्यूज

दुर्ग। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के निर्देशानुसार सुरक्षित बचपन अभियान के अंतर्गत शनिवार को शिक्षकों के लिए एक दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय भवन, दुर्ग के चतुर्थ तल स्थित नवीन कॉन्फ्रेंस हॉल में किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षकों को बाल अधिकारों, बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों, यौन शोषण की पहचान, साइबर अपराधों से सुरक्षा तथा बच्चों को समय पर विधिक एवं संस्थागत सहायता उपलब्ध कराने के संबंध में प्रशिक्षित एवं जागरूक करना था।



कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग के अध्यक्ष के विनोद कुजूर, कुटुम्ब न्यायालय की प्रधान न्यायाधीश सुमन एक्का एवं प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री शेख अशरफउपस्थित रहे। कार्यक्रम में न्यायिक अधिकारियों, संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों, विभिन्न विद्यालयों से आए शिक्षकों तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चयनित ग्रामों में कार्यरत सामुदायिक मध्यस्थों की विशेष सहभागिता रही।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा केवल परिवार अथवा प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि विद्यालय और शिक्षक भी इस दायित्व के महत्वपूर्ण सहभागी हैं। शिक्षक बच्चों के व्यवहार, परिस्थितियों एवं भावनात्मक परिवर्तनों को निकटता से समझते हैं, इसलिए किसी भी प्रकार की प्रताड़ना, शोषण अथवा असुरक्षा की स्थिति की पहचान कर समय पर उचित कदम उठाने में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने बाल अधिकारों के संरक्षण को सामाजिक एवं संस्थागत प्राथमिकता बनाने पर बल दिया।

कार्यक्रम के अंतर्गत साइबर सेल के डॉ संकल्प राय द्वारा ऑनलाइन सुरक्षा, साइबर ग्रूमिंग, साइबर बुलिंग एवं सेक्सटॉर्शन जैसे गंभीर विषयों पर व्यावहारिक जानकारी प्रदान की गई। डिजिटल माध्यमों के बढ़ते उपयोग के बीच बच्चों को ऑनलाइन शोषण, साइबर अपराधों एवं अनुचित संपर्कों से सुरक्षित रखने के लिए शिक्षकों की सतर्कता और डिजिटल जागरूकता को आवश्यक बताया गया।

इसके पश्चात रवि कुमार महोबिया, द्वारा बाल शोषण की पहचान, बच्चे की शिकायत पर संवेदनशील एवं उचित प्रतिक्रिया, व्यक्तिगत सुरक्षा, सुरक्षित एवं असुरक्षित स्पर्श, व्यक्तिगत सीमाओं तथा किसी बच्चे द्वारा शोषण की घटना बताए जाने पर शिक्षक की भूमिका के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। उन्होंने बच्चों को अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक बनाने और उनके द्वारा व्यक्त की गई शिकायतों को गंभीरता से लेने की आवश्यकता पर बल दिया। सुषमा लकड़ा, अध्यक्ष, स्थायी लोक अदालत, दुर्ग द्वारा विद्यालयों में शिक्षक प्रभारी की भूमिका, विधिक साक्षरता क्लब की स्थापना एवं उनके माध्यम से संचालित की जाने वाली मासिक गतिविधियों के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान किया गया। उन्होंने विद्यालयों में विधिक जागरूकता को नियमित गतिविधि के रूप में विकसित करने तथा बच्चों को उनके अधिकारों, कर्तव्यों एवं सुरक्षित व्यवहार के प्रति जागरूक बनाने पर जोर दिया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग द्वारा इस पहल के माध्यम से बाल अधिकारों के संरक्षण, बच्चों के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम, शिक्षकों की क्षमता संवर्धन तथा विद्यालय स्तर पर विधिक जागरूकता को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किया गया।

Since 1972
CROWN®-TV
Choice Of Millions
LED / Washing Machine
Cooler / Fridge
Available All Size
CONTACT :
Atlas Radio Traders (Crown)
Sect.-3, D-48, Ward No. 13
Devendra Nagar, Raipur (C.G.) 492009
Near Akash Gas Agency Line
Mob.: 98262 52372

खास खबर

जनगणना 2027 की तैयारियां समयबद्ध एवं सुव्यवस्थित ढंग से करें- कलेक्टर

कांकेर। कलेक्टर कुन्दन कुमार ने आज जिले के सभी एसडीएम, जनगणना चार्ज अधिकारी, तहसीलदार एवं नगरीय निकायों के मुख्य नगरपालिका अधिकारियों की बैठक लेकर जनगणना 2027 की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने जनसंख्या गणना कार्य को सुचारू, व्यवस्थित एवं समयबद्ध ढंग से संपन्न कराने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। कलेक्टर ने निर्देशित किया कि जनगणना कार्य में एकल शिक्षकीय संस्थाओं के शिक्षकों, गर्भवती महिलाओं एवं दिव्यांगजनों की ड्यूटी नहीं लगाई जाए। मान्यता प्राप्त निजी शैक्षणिक संस्थाओं के कर्मचारियों की ड्यूटी भी जनगणना कार्य में लगाई जा सकती है। जनगणना कार्य के लिए ड्यूटी लगाए जाने वाले कर्मचारियों एवं रिजर्व कर्मचारियों का पहले से चिन्हांकन करने के निर्देश दिए गए। सभी तहसीलदार एवं नगरीय निकायों के अधिकारियों को टीम के प्रत्येक सदस्य का आंकलन कर निर्धारित मापदंड के अनुसार पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने को कहा गया। उन्होंने कहा कि जनगणना कार्य में नियुक्त प्रगणक धैर्यवान एवं जिम्मेदार होना चाहिए। बैठक में बताया गया कि फील्ड ट्रेनर्स का तीन दिवसीय प्रशिक्षण 02 से 12 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा।

जेवरतला रोड पर बनेगा नवीन महाविद्यालय भवन, विद्यार्थियों को मिलेगा बेहतर शैक्षणिक वातावरण

बालोद। जिले में उच्च शिक्षा की सुविधाओं के विस्तार और विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। इसी कड़ी में जेवरतला रोड पर नवीन महाविद्यालय भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मंशानुरूप तथा लोक निर्माण विभाग मंत्री अरुण साव के नेतृत्व में शैक्षणिक अधोसंरचना को मजबूत बनाने के लिए कार्य किया जा रहा है। कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा के निर्देशानुसार जिले में निर्माण कार्यों की प्रगति और गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में संबंधित महाविद्यालय का संचालन स्कूल भवन में किया जा रहा है। इससे विद्यार्थियों को महाविद्यालयीन अध्ययन के लिए आवश्यक सुविधाओं और पर्याप्त स्थान की उपलब्धता में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नवीन महाविद्यालय भवन के निर्माण से विद्यार्थियों को अपना परिसर मिलेगा, जहां पढ़ाई के लिए बेहतर और व्यवस्थित वातावरण उपलब्ध हो सकेगा। छत्तीसगढ़ शासन के लोक निर्माण विभाग, संभाग बालोद द्वारा इस भवन निर्माण कार्य के लिए 415.62 लाख रुपए की अनुबंध राशि निर्धारित की गई है। कार्य की अनुबंध अवधि 15 माह रखी गई है। इस कार्य के लिए अनुबंध जारी किया गया है तथा निर्माण कार्य प्रगति पर है। महाविद्यालय का अपना भवन बनने से विद्यार्थियों को स्कूल भवन पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। महाविद्यालय की शैक्षणिक आवश्यकताओं के अनुरूप 415.62 लाख रुपए की लागत वाले भवन तैयार होने से कक्षाओं के संचालन, अध्ययन-अध्यापन और अन्य शैक्षणिक गतिविधियों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इससे छात्र-छात्राओं को पढ़ाई के लिए अनुकूल वातावरण मिलेगा और उच्च शिक्षा के प्रति उनका उत्साह भी बढ़ेगा। नवीन महाविद्यालय भवन का निर्माण क्षेत्र में उच्च शिक्षा की सुविधाओं के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक संसाधन उपलब्ध होने के साथ ही क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

गांव की बिजली से गांव का विकास, यही ग्रामीण आत्मनिर्भरता का नया मॉडल : मुख्यमंत्री साय

मुख्यमंत्री साय ने कुंजारा में 2 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित प्रदेश के पहले पंचायत आधारित 280 किलोवाट ऑन-ग्रिड सौर ऊर्जा संयंत्र का किया लोकार्पण

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि गांवों की वास्तविक आत्मनिर्भरता तभी संभव है, जब ग्राम पंचायतों के पास विकास कार्यों के लिए आय के अपने स्थायी स्रोत हों। जशपुर जिले की ग्राम पंचायत कुंजारा ने सौर ऊर्जा के माध्यम से इस दिशा में एक नई मिसाल प्रस्तुत की है। अब कुंजारा न केवल बिजली का उत्पादन करेगा, बल्कि उससे होने वाली आय का उपयोग गांव के विकास में भी कर सकेगा। यह पहल प्रदेश की अन्य ग्राम पंचायतों के लिए भी प्रेरणादायी बनेगी। मुख्यमंत्री साय जशपुर जिले के कुनकुरी विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत कुंजारा में 2 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित 280 किलोवाट क्षमता के ऑन-ग्रिड सौर ऊर्जा संयंत्र का लोकार्पण कर रहे थे। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत स्थापित यह छत्तीसगढ़ की अपनी तरह की पहली परियोजना है, जिसमें सौर ऊर्जा उत्पादन के माध्यम से ग्राम पंचायत को नियमित आय उपलब्ध कराकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की व्यवस्था की गई है।





वर्चुअल नेट मीटरिंग से शासकीय कार्यालयों के बिजली बिल में होगी बचत

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से जिला पंचायत जशपुर के प्रस्ताव पर कुंजारा में 2 करोड़ रुपये की लागत से 280 किलोवाट क्षमता का ऑन-ग्रिड सौर ऊर्जा संयंत्र स्वीकृत किया गया है। इस संयंत्र की स्थापना छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) द्वारा उच्च दक्षता वाली आधुनिक तकनीक के माध्यम से की गई है। परियोजना के अंतर्गत सौर संयंत्र से उत्पादित बिजली सीधे ग्रिड में प्रवाहित होगी। उत्पादन की गणना के लिए संयंत्र स्थल पर नेट मीटर लगाया गया है, जिससे प्रतिदिन उत्पादित विद्युत यूनिटों का लेखा-जोखा रखा जाएगा।

अन्य ग्राम पंचायतों के लिए रोल मॉडल बनेगा कुंजारा

कुंजारा में स्थापित यह सौर ऊर्जा संयंत्र ग्राम पंचायतों की आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में एक अभिनव प्रयोग है। अब तक ग्राम पंचायतों को अधिकांश विकास कार्यों के लिए शासकीय अनुदान एवं विभिन्न योजनाओं से प्राप्त राशि पर निर्भर रहना पड़ता था। इस परियोजना से ग्राम पंचायत को नियमित आय का एक स्थायी स्रोत उपलब्ध होगा। सौर ऊर्जा से अर्जित आय का उपयोग ग्राम सभा की सहमति से स्थानीय विकास और जनसुविधाओं के विस्तार में किया जा सकेगा। इससे पंचायत की वित्तीय क्षमता मजबूत होगी और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकास कार्यों को गति मिलेगी। कुंजारा की इस पहल की सफलता से प्रदेश की अन्य ग्राम पंचायतों को भी सौर ऊर्जा उत्पादन के माध्यम से आय के नए स्रोत विकसित करने की प्रेरणा मिलेगी। यह मॉडल भविष्य में ग्रामीण स्वावलंबन और विकेंद्रीकृत विकास की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

मुख्यमंत्री साय ने ग्रामवासियों को इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए बधाई देते हुए कहा कि कुंजारा अब बिजली उत्पादन के साथ आय अर्जित करने वाली ग्राम पंचायत के रूप में नई पहचान बनाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौर ऊर्जा के माध्यम से देश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का जो संकल्प लिया है, कुंजारा की यह परियोजना उसी संकल्प को गांव की धरती पर साकार करने का उदाहरण है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यह सौर ऊर्जा संयंत्र प्रतिवर्ष लगभग 4 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन करने में सक्षम होगा। संयंत्र से उत्पादित बिजली सीधे विद्युत ग्रिड में प्रवाहित की जाएगी। वर्चुअल नेट मीटरिंग के माध्यम से इस बिजली का समायोजन जिले के विभिन्न शासकीय कार्यालयों की विद्युत खपत से किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायत कुंजारा को 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से लाभांश प्राप्त होगा। इससे ग्राम पंचायत को सालाना अनुमानित 18.75 लाख रुपये की आय होगी। इस राशि का उपयोग ग्राम सभा के प्रस्ताव के आधार पर गांव की आवश्यकताओं, अधोसंरचना निर्माण और स्थानीय विकास कार्यों में किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना ग्राम पंचायतों को अपनी आय के स्रोत विकसित करने की नई दिशा दिखाएगी। आने वाले समय में कुंजारा प्रदेश की अन्य पंचायतों के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता का रोल मॉडल बनेगा।

मुख्यमंत्री साय ने कार्यक्रम में ग्रामवासियों की मांगों पर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने ग्राम पंचायत कुंजारा में 20 लाख रुपये की लागत से सीसी सड़क निर्माण, श्री टोली में सामुदायिक भवन निर्माण तथा कुंजारा में शिव मंदिर के समीप सामुदायिक भवन निर्माण की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और गांवों को विकास के नए अवसरों से जोड़ने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। सड़क, सामुदायिक भवन और अन्य आवश्यक अधोसंरचनाओं के विकास से ग्रामीणों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सौर ऊर्जा भविष्य की ऊर्जा है। इससे जहां पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलता है, वहीं बिजली पर होने वाले खर्च में भी बचत होती है। उन्होंने ग्रामीणों से प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ते अवसरों का लाभ गांवों और आम नागरिकों तक पहुंचाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। कुंजारा की यह पहल दर्शाती है कि आधुनिक तकनीक और स्थानीय संसाधनों के बेहतर उपयोग से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती दी जा सकती है।

जशपुर जिले के विभिन्न शासकीय कार्यालयों के विद्युत मीटरों को वर्चुअल नेट मीटरिंग व्यवस्था के अंतर्गत छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड से अनुबंधित किया गया है। इस व्यवस्था से सौर संयंत्र द्वारा ग्रिड में प्रवाहित बिजली का समायोजन संबंधित शासकीय कार्यालयों की विद्युत खपत के साथ किया जाएगा। इससे शासकीय कार्यालयों के बिजली बिल में उल्लेखनीय कमी आएगी। इस बचत में से निर्धारित लाभांश 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से ग्राम पंचायत कुंजारा के खाते में नियमित रूप से जमा किया जाएगा। परियोजना के संचालन एवं लाभांश वितरण के संबंध में विद्युत विभाग, ग्राम पंचायत कुंजारा और जनपद पंचायत कुनकुरी के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) भी किया गया।

इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष सालिक साय, पूर्व विधायक रोहित साय, उपेंद्र यादव, ग्राम पंचायत कुंजारा के सरपंच, पुलिस महानिरीक्षक दीपक कुमार झा, कलेक्टर रोहित व्यास, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिषेक कुमार सहित जनप्रतिनिधिगण, प्रशासनिक अधिकारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे।

एकलव्य विद्यालय छर्राटांगर में तीन दिवसीय 'उद्भव 2026' का भव्य हुआ शुभारंभ

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायगढ़। जनजातीय कला, संस्कृति, संगीत, नृत्य और साहित्य को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय छर्राटांगर घरघोड़ा में तीन दिवसीय संकुल स्तरीय सांस्कृतिक एवं साहित्यिक उत्सव 'उद्भव 2026' का भव्य शुभारंभ हुआ। 28 से 30 नवंबर तक आयोजित इस उत्सव में रायगढ़ संकुल के अंतर्गत आने वाले 8 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के विद्यार्थी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्सव की थीम 'विरासत, संस्कृति एवं राष्ट्रीय एकता' रखी गई है, जिसके माध्यम से जनजातीय परंपराओं, सांस्कृतिक विविधता और आपसी एकता का संदेश दिया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में लोकसभा सांसद राधेश्याम राठिया उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथियों में जनपद सदस्य श्रीमती अंबिका मुकेश राठिया, सरपंच छर्राटांगर श्रीमती सुखमती राठिया, घनश्याम राठिया सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की वंदना के साथ हुआ। इसके पश्चात राष्ट्रगान एवं विद्यार्थियों द्वारा स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। अतिथियों का पुष्पगुच्छ भेंटकर स्वागत एवं सम्मान किया गया। छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक सौंदर्य को दर्शाते राज्यगीत 'अरपा पैरी के धार' की प्रस्तुति



ने उपस्थित जनसमूह को भावविभोर कर दिया। उत्सव के पहले दिन विद्यार्थियों ने जनजातीय वाद्ययंत्रों पर आधारित सामूहिक संगीत की मनमोहक प्रस्तुति दी। पारंपरिक वाद्ययंत्रों की मधुर धुनों ने जनजातीय संगीत की समृद्ध परंपरा को जीवंत कर दिया। वहीं नाटक के माध्यम से विद्यार्थियों ने अपनी अभिनय प्रतिभा एवं रचनात्मकता का परिचय दिया। ऑर्केस्ट्रा की आकर्षक प्रस्तुति ने भी कार्यक्रम में संगीत और उत्साह का रंग भर दिया। उत्सव के आगामी दो दिनों में जूनियर एवं सीनियर वर्ग के विद्यार्थियों के लिए समूह नृत्य, एकल नृत्य, गायन, वाद्य संगीत, चित्रकला, वाद-विवाद, भाषण, प्रश्नोत्तरी, नाटक, रचनात्मक लेखन और पारंपरिक कहानी वाचन जैसी विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से विद्यार्थी अपनी कलात्मक, साहित्यिक एवं बौद्धिक प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। साथ ही विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों को एक-दूसरे की कला, संस्कृति और परंपराओं को जानने का अवसर मिलेगा।

आधुनिक तकनीक के साथ चिकित्सक का मानवीय स्पर्श भी जरूरी - राज्यपाल

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका ने कहा कि आधुनिक चिकित्सा तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता रोगों के निदान एवं उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, लेकिन तकनीक चिकित्सक के अनुभव, मानवीय संवेदनशीलता और शारीरिक परीक्षण का विकल्प नहीं हो सकती। चिकित्सा सेवा में तकनीक के साथ मानवीय स्पर्श और रोगी के प्रति संवेदनशील व्यवहार भी आवश्यक है।

राज्यपाल डेका ने आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), रायपुर में इंडियन रेडियोलॉजिकल एंड इमेजिंग एसोसिएशन (आईआर आईए), छत्तीसगढ़ राज्य शाखा के 16वें वार्षिक सम्मेलन का शुभारंभ अवसर पर उक्त बातें कही। इस अवसर पर एम्स रायपुर के कार्यपालक निदेशक एवं सीईओ लेफ्टिनेंट जनरल अशोक जिंदल, आइ आर आइ ए के अध्यक्ष डॉ पुष्पराज भटले, छत्तीसगढ़ चौप्टर के अध्यक्ष डॉ नरेंद्र के. बूधे सहित वरिष्ठ रेडियोलॉजिस्ट, फैकल्टी सदस्य और रेजिडेंट डॉक्टर उपस्थित थे। राज्यपाल ने दीप



प्रज्वलित कर सम्मेलन का शुभारंभ किया।

अपने उद्बोधन में राज्यपाल ने कहा कि एक्स-रे का आविष्कार चिकित्सा विज्ञान में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। रेडियोलॉजी ने रोगों की पहचान और उपचार को नई दिशा दी है। आज यह क्षेत्र एक्स-रे से आगे बढ़कर अल्ट्रासाउंड, एमआरआई और अन्य अत्याधुनिक इमेजिंग तकनीकों तक पहुंच चुका है। इन तकनीकों ने चिकित्सा निदान को अधिक प्रभावी बनाया है।

श्री डेका ने कहा कि चिकित्सकों को तकनीक का उपयोग विवेक और संवेदनशीलता के साथ करना चाहिए।कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक सर्जरी और आधुनिक उपकरण चिकित्सा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इनके पीछे मानव मस्तिष्क, कौशल और अनुभव की भूमिका सर्वोपरि है। चिकित्सकों को तकनीक का उपयोग विवेक और संवेदनशीलता के साथ करना चाहिए।

राज्यपाल ने रोगियों के शारीरिक परीक्षण के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि चिकित्सक का रोगी से संवाद, परीक्षण और संवेदनशील व्यवहार उसके मन में भरोसा पैदा करता है। आधुनिक इमेजिंग तकनीक के साथ चिकित्सकीय अनुभव और सूक्ष्म अवलोकन भी सटीक निदान के लिए जरूरी हैं। उन्होंने प्रसिद्ध चिकित्सक डॉ. बिधानचंद्र रॉय का उदाहरण देते हुए चिकित्सकीय अंतर्दृष्टि और अनुभव के महत्व को रेखांकित किया। राज्यपाल ने कहा कि ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में इंटरनेट तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी तकनीकें समय पर चिकित्सा परामर्श और उपचार उपलब्ध कराने में सहायक हो सकती हैं। विशेषकर आपातकालीन परिस्थितियों में इनका उपयोग जीवनरक्षक साबित हो सकता है।

श्री डेका ने डिजिटल लत और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियों पर भी चिंता व्यक्त की। राज्यपाल ने तकनीक के संतुलित उपयोग, मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता तथा जरूरत पड़ने पर परामर्श लेने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं पर खुलकर बात करना और समय पर सहायता लेना जरूरी है। राज्यपाल ने चिकित्सकों से रोगियों के साथ विश्वासपूर्ण संवाद स्थापित करने तथा रोगियों को अपनी समस्याएं खुलकर बताने का अवसर देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि चिकित्सा सेवा केवल उपचार तक सीमित नहीं है, बल्कि संवेदनशीलता, विश्वास और सेवा भावना भी इसका अभिन्न अंग हैं।

स्थानीय बोली-भाषा में शिक्षा से बच्चों की मौलिक प्रतिभा और व्यक्तित्व का होगा बेहतर विकास : ओपी चौधरी

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि हमारी स्थानीय बोली-भाषाएं हमारी सांस्कृतिक समृद्धि और गौरवशाली विरासत की पहचान हैं। इनका संरक्षण, संवर्धन और मान बढ़ाना हम सभी की जिम्मेदारी है। बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा उनकी स्थानीय बोली-भाषा में होने से उनकी सीखने की क्षमता, बौद्धिक विकास, आत्मविश्वास और मौलिक प्रतिभा को बढ़ावा मिलता है। हमें अपनी भाषा और संस्कृति पर गर्व करते हुए आने वाली पीढ़ियों को इनसे जोड़ने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए।

वित्त मंत्री चौधरी रायपुर के न्यू सर्किट हाउस स्थित कन्वेंशन हॉल में छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने छत्तीसगढ़ सहित देश-दुनिया के विभिन्न हिस्सों में निवासरत



छत्तीसगढ़िया भाई-बहनों को राजभाषा दिवस की गाड़ा-गाड़ा बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। समारोह में स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव भी शामिल हुए।

इस अवसर पर वित्त मंत्री चौधरी ने पुस्तक प्रदर्शनी का अवलोकन किया। प्रदर्शनी में सिक्किम की विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्रों, बस्तरिया पत्र-पत्रिकाओं तथा छत्तीसगढ़ के समृद्ध साहित्य को देखने और समझने का अवसर मिला। समारोह में साहित्यकारों को सम्मानित किया गया तथा 14 लेखक-लेखिकाओं की पुस्तकों का विमोचन हुआ। श्री चौधरी ने सम्मानित साहित्यकारों और रचनाकारों को बधाई देते हुए छत्तीसगढ़ी भाषा एवं साहित्य के संवर्धन के लिए निरंतर कार्य करते रहने की शुभकामनाएं दीं।

वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा में उनकी स्थानीय भाषा के साथ-साथ स्थानीय बोली का विशेष महत्व है। जब बच्चे अपनी परिचित बोली में सीखना शुरू करते हैं, तो उनमें विषयों को समझने, स्वतंत्र रूप से सोचने और अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की क्षमता विकसित होती है। इससे उनके आत्मविश्वास, धैर्य, बौद्धिक क्षमता और व्यक्तित्व का बेहतर विकास होता है। सीखने की मजबूत बुनियाद तैयार होने के बाद बच्चे अन्य भाषाओं को भी आसानी से सीख सकते हैं।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लाई गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में मातृभाषा और स्थानीय भाषा में प्रारंभिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने के पीछे वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। शिक्षा का उद्देश्य केवल बच्चों को परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए तैयार करना नहीं, बल्कि उनकी मौलिक सोच, रचनात्मकता और नैसर्गिक क्षमताओं को विकसित करना भी होना चाहिए।

वित्त मंत्री चौधरी ने अपने विद्यार्थी जीवन के अनुभवों को साझा करते हुए बताया कि उन्होंने गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाई की और 18 वर्ष की उम्र तक गांव में ही रहे। बचपन में परिवार के सदस्य उन्हें पाठ रटने के बजाय समझने और अपने शब्दों में लिखने के लिए प्रेरित करते थे। उन्होंने तीसरी कक्षा की एक घटना का उल्लेख करते हुए बताया कि परीक्षा में सुबह जल्दी उठने के लाभ से संबंधित प्रश्न का उत्तर उन्होंने अपने अनुभवों और कल्पनाओं के आधार पर लिखा था। निर्धारित उत्तर से अलग लिखने पर शिक्षक ने उन्हें डांटा, लेकिन विद्यालय के प्रधानपाठक ने उनकी मौलिक अभिव्यक्ति को समझा और अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से लिखने के लिए प्रोत्साहित किया।

श्री चौधरी ने बताया कि प्रारंभ में वे आधी हिंदी और आधी छत्तीसगढ़ी में अपने विचार लिखते थे। धीरे-धीरे उन्होंने हिंदी में लिखना सीखा और आवश्यकता के अनुरूप अंग्रेजी भी सीखी। पत्र लेखन, निबंध लेखन और भाषण प्रतियोगिताओं में भाग लेने से उनकी अभिव्यक्ति क्षमता निरंतर विकसित होती गई। उन्होंने बताया कि इसी मौलिक लेखन क्षमता और निरंतर अभ्यास के परिणामस्वरूप उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा के निबंध प्रश्नपत्र में देशभर में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए।

GST NO. 22AHMPB9621P1Z2
PH.: 0788-4060131





अनुप ट्रेडर्स
आर्टिफिशियल ज्वेलरी के विक्रेता
लिंक रोड, केम्प-2, पावर हाउस, भिलाई
मो. 09826389666, 8839749539

गंजेपन से मुक्ति मात्र 1 घंटे में
COMPLETE FAMILY SALON
हेयर रिप्लेसमेंट, 100% संतुष्टि की गारंटी



JITU'Z
CUT N SHINE
93009-11331
रंगोली बैंगल्स के सामने, जयसवाल इलेक्ट्रानिक के बाजू में इंदिरा मार्केट, स्टेशन रोड, दुर्ग (छ.ग.)

कृति के बॉसी अंदाज पर फिदा हुए फैंस

ब्लैक एंड व्हाइट आउटफिट में दिखीं बेहद सुंदर

GQ इंडिया के 'मेन ऑफ द ईयर अवॉर्ड्स 2026' के इस इवेंट में कृति सेनन समेत कई कलाकार नजर आए। किसी ने अपने शानदार आउटफिट से लोगों का ध्यान खींचा तो किसी ने अपने खास अंदाज से महफिल लूट ली। अवॉर्ड सेरेमनी में एक्ट्रेस कृति सेनन ने शानदार आउटफिट पहना था जिसकी चर्चा पूरे सोशल मीडिया पर होने लगी।



अब इसके बाद एक्ट्रेस ने अपनी तस्वीरें इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट की हैं, जिनमें कृति काफी खूबसूरत नजर आ रही हैं। इन फोटोज को पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा- मिशन पूरा हुआ।

कृति सेनन ब्लैक एंड व्हाइट आउटफिट में नजर आईं। उन्होंने व्हाइट शर्ट के साथ ब्लैक पैंट और मैचिंग जैकेट पहनी थी। उनके आउटफिट में गोल्डन डिटेलिंग भी देखने को मिली।

स्लाइड्स की शुरुआत में एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो नजर आती है, जिसमें कृति काफी कूल लग रही हैं। आगे नजर आ रही कुछ तस्वीरों में वे मैकअप करवाती भी दिख रही हैं। इसके साथ आखिरी की तस्वीरों में कृति पिज्जा खाती और कूल पोज देती दिख रही हैं।

कृति की इन खूबसूरत तस्वीरों पर फैंस भी जमकर प्यार बरसा रहे हैं।

किसी ने दिल वाले इमोज शेयर कर प्यार लुटाया तो किसी ने 'बॉसी वाइब्स' और 'लेडी बॉस' कमेंट किया। वहीं कई यूजर्स ने उन्हें बहुत सुंदर बताया।

मानसिक स्वास्थ्य को प्राकृतिक रूप से बेहतर करने के लिए अपनाएं ये तरीके

मानसिक स्वास्थ्य शरीर की तरह ही जरूरी होता है, लेकिन इसे नजरअंदाज करने की गलती न करें। तनाव, चिंता और उदासी जैसी समस्याएं आजकल आम हो गई हैं। इन समस्याओं का इलाज दवाओं से ज्यादा प्राकृतिक उपायों पर निर्भर होना चाहिए। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे प्राकृतिक तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं और जीवन में खुशी और संतुलन पा सकते हैं।

नियमित एक्सरसाइज करें

एक्सरसाइज न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। रोजाना 30 मिनट टहलने, दौडऩे या योग करने से आपका मन शांत रहता है और तनाव कम होता है।

इसके अलावा एक्सरसाइज से कुछ ऐसे हार्मोन निकलते हैं, जो आपको खुश रखते हैं। नियमित एक्सरसाइज करने से नींद भी बेहतर होती है और आप दिनभर ऊर्जा से भरपूर महसूस करते हैं।

संतुलित खाना खाएं

आपका खाना आपके मानसिक स्वास्थ्य पर बड़ा असर डाल सकता है। कुछ खास पोषक तत्वों से भरपूर आहार लेने से आपका मन खुश रहता है और उदासी जैसी समस्याओं से बचाव होता है।

हरी सब्जियां, फल, नट्स और साबुत अनाज अपने खाने में शामिल करें। इसके अलावा पर्याप्त पानी पीना भी जरूरी है ताकि आपका दिमाग तरोताजा रहे और अच्छी तरह काम कर सके।

ध्यान और सांस की तकनीकें अपनाएं

ध्यान और सांस की कुछ तकनीकें आपके मन को शांत करने में मदद करती हैं। सुबह-सुबह या शाम को कुछ मिनट ध्यान करने से आप अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं और मानसिक शांति पा सकते हैं।

सांस की तकनीकों से आपकी सांसों की गति संतुलित रहती है, जिससे तनाव कम होता है और ऊर्जा बढ़ती है। इन दोनों तकनीकों को नियमित रूप से अपनाने से मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है और आप अधिक सकारात्मक महसूस करते हैं।

पर्याप्त नींद लें

नींद पूरी न होने पर आपका मन चिड़चिड़ा हो जाता है और आप किसी भी काम पर ध्यान नहीं दे पाते। इसलिए हर रोज 7-8 घंटे की नींद लेना बहुत जरूरी है। सोने से पहले मोबाइल या टीवी देखने से बचें क्योंकि इनसे आपकी नींद प्रभावित होती है। एक आरामदायक बिस्तर और शांत माहौल में सोना बेहतर होता है।

सोने का नियमित समय निर्धारित करें ताकि आपका शरीर भी उसी समय पर सोने के लिए तैयार हो सके।

दोस्तों और परिवार से जुड़े रहें

दोस्तों और परिवार वालों से जुड़े रहना बहुत जरूरी होता है ताकि आप अकेलापन महसूस न करें।

समय-समय पर उनसे मिलना या फोन पर बात करना आपके मनोबल को बढ़ाता है और आपको खुश रखता है।

इन 5 तरीकों को अपनाकर आप अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं और जीवन में खुशी एवं संतुलन पा सकते हैं। प्राकृतिक उपायों से इलाज करना न केवल सस्ता होता है बल्कि ज्यादा असरदार भी होता है।





तारा सुतारिया की जन्मदिन पोस्ट पर वीर पहाड़िया ने लुटाया प्यार

लोग बोले- पैचअप कर लो

तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया के रिश्ते में भले ही खटास आ जाने की चर्चा हो, लेकिन फैंस को वापस से उनके एक होने का बेसब्री से इंतजार है। हाल ही में, जब सोशल मीडिया पर्सनैलिटी ओरी ने अभिनेत्री के जन्मदिन की पोस्ट साझा की, तो उस पर वीर की प्रतिक्रिया देखकर लोग हैरान रह गए। अब फैंस कमेंट के जरिए अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं और चाहते हैं कि तारा और वीर पैचअप कर लें।

तारा ने 19 नवंबर को अपना जन्मदिन मनाया जिसका हिस्सा बनने सिनेमा के कई सितारे पहुंचे।

ओरी भी इस जश्न का हिस्सा बने और उन्होंने अभिनेत्री के जन्मदिन का एक वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर साझा किया।

जन्मदिन की बधाइयों ने तो फैंस का ध्यान खींचा ही, लेकिन कमेंट सेक्शन में वीर की अचानक मौजूदगी ने लोगों के बीच हलचल मचा दी।

अभिनेता ने जन्मदिन केक के साथ एक सफेद दिल वाला इमोजी साझा किया था।

वीर के कमेंट के बाद, लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि क्या दोनों एक-दूसरे को फिर मौका दे रहे हैं। वहीं, कुछ ने उन्हें पैचअप करने की सलाह दे डाली।

तारा और वीर ने पिछले साल डेटिंग शुरू की थी। फिर उसी साल जुलाई में उनका रिश्ता सार्वजनिक हो गया।

जनवरी, 2026 में अचानक उनके ब्रेकअप की खबरों ने जोर पकड़ लिया था। हालांकि, दोनों में से किसी ने भी कथित अलगाव की बात पर मुहर नहीं लगाई है।

65 हजार की साड़ी में नजर आई तमन्ना सदगुरु के समारोह में की थी शिरकत

अभिनेत्री तमन्ना भाटिया और फिल्म निर्माता विशाल भारद्वाज के साथ हाल ही में सद्गुरु की फोटो बुक पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। 'डिसअपीयरिंग फेसेस' नामक यह पुस्तक आध्यात्मिक गुरु की 50 वर्षों की यात्रा के दौरान खींची गई तस्वीरों का संग्रह है।

तस्वीरों में छाईं तमन्ना भाटिया

सद्गुरु के इस इवेंट में तमन्ना भाटिया काफी स्टाइलिश अंदाज में पहुंचीं थी। खूबसूरत सी पिंक साड़ी में पहुंचीं अभिनेत्री ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा था। फूलों के हैंडप्रिंटिंग और मोतियों की बारीक डिटेलिंग वाली इस हल्के गुलाबी रंग की साड़ी में एक्ट्रेस बेहद सुंदर लग रही थीं। करीब 65000 हजार कीमत वाली इस साड़ी को फैशन ब्रांड पिचिका ने डिजाइन किया है। साड़ी की सबसे खास बात यह है कि इस पर फूलों की प्रिंटिंग मशीन के बजाय हाथों से की गई है।

सदगुरु के आध्यात्मिक यात्रा पर चर्चा

इस समारोह मुंबई स्थित होटल में आयोजित हुआ। इस दौरान सद्गुरु की फोटो बुक 'डिसअपीयरिंग फेसेस' को लेकर एक खास चर्चा रखी गई थी। इस बुक में सद्गुरु की हिमालय और तिब्बत के दौरान यात्रा की फोटोज हैं। अपनी यात्रा में सद्गुरु कई साल तक उत्तर भारत में घूमते रहे।

योग केंद्र जाती हैं तमन्ना

तमन्ना का सद्गुरु के पैर छूकर आशीर्वाद लेना उनके आध्यात्मिक झुकाव को देखते हुए कोई नई बात नहीं है। एक्ट्रेस कई मौकों पर भगवान शिव के प्रति अपनी श्रद्धा जाहिर कर चुकी हैं। वह कोयंबटूर स्थित सद्गुरु के ईशा योग केंद्र भी जाती रहती हैं। तमन्ना यहां महाशिवरात्रि के आयोजन में भी शामिल हो चुकी हैं और प्रसाद चढ़ाने की रस्म में हिस्सा ले चुकी हैं। उनकी भगवान शिव के प्रति आस्था का असर उनके फिल्मी किरदारों में भी देखने को मिला है। तमन्ना तेलुगु फिल्म 'ओडेला 2' में भगवान शिव की भक्त के किरदार में नजर आई थीं।



अरशद वारसी की असुर 3 में सपना पब्बी हुईं शामिल, रिलीज को लेकर आया अपडेट

अरशद वारसी और बरुन सोबती की सीरीज असुर के अब तक 2 सीजन आ चुके हैं। इसका तीसरा सीजन अपने प्रोडक्शन चरण में है और शूटिंग इन दिनों मुंबई में चल रही है, जिसके 28 दिसंबर तक खत्म होने की उम्मीद की जा रही है। गौरव शुक्ला ने साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर के निर्देशन की कमान उठाई है। ताजा अपडेट है कि सपना पब्बी सीरीज का हिस्सा बन गई हैं, जिन्हें बॉबी देओल की फिल्म बंदर में देखा गया था।



सपना के मुताबिक, सपना इस सीरीज में मुख्य कलाकारों के साथ शामिल हुई हैं और उन्हें शारिब हाशमी, रिद्धि डोगरा और अमेय वाघ के साथ एक जांचकर्ता के किरदार में देखा जाएगा।

उनके पहले, परियोजना से एहसास चन्ना, श्वेता बसु प्रसाद और संदीपा धर के जुडऩे की चर्चा भी थी। हालांकि, निर्माताओं की ओर से कास्टिंग पर आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है।

शूटिंग शेड्यूल प्लान के अनुसार, असुर 3 की शूटिंग 28 दिसंबर तक पूरी हो सकती है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि असुर 3 को जुलाई, 2027 तक रिलीज करने का लक्ष्य है।

सूत्र ने कहा, जियोहॉटस्टार के बड़े स्पोर्ट्स प्रोग्रामिंग कैलेंडर को ध्यान में रखते हुए असुर 3 का प्रीमियर 2027 में इंडियन प्रीमियर लीग सीजन खत्म होने के बाद होने की उम्मीद है। हालांकि, सही तारीख पोस्ट-प्रोडक्शन शेड्यूल पर निर्भर करेगी, लेकिन निर्माता क्यू3 रिलीज का लक्ष्य बना रहे हैं।

कहानी की शुरुआत वहीं से होगी, जहां इसका दूसरा सीजन खत्म हुआ था।

कामकाजी महिलाओं के लिए आसान और प्रभावी हैं ये पांच आदतें बालों की देखभाल से जुड़ी

आजकल की कामकाजी महिलाओं के पास समय की कमी होती है, लेकिन इसके बावजूद अपने बालों की देखभाल करना जरूरी है। सही हेयर केयर रूटीन अपनाकर आप अपने बालों को स्वस्थ और चमकदार रख सकती हैं। इस लेख में हम कुछ आसान और प्रभावी हेयर केयर आदतों के बारे में जानेंगे, जो आपके बालों को मजबूती देंगे और उन्हें टूटने से बचाएंगे। इन सुझावों को अपनाकर आप अपने बालों को प्राकृतिक तरीके से स्वस्थ रख सकती हैं।



नियमित रूप से तेल मालिश करें

बालों को टूटने से बचाने के लिए नियमित रूप से तेल मालिश करना बहुत जरूरी है।

नारियल या बादाम के तेल का उपयोग करें और हल्के हाथों से सिर की मालिश करें। इससे खून का दौरा बढ़ता है और बालों की जड़ों को मजबूती मिलती है।

हफ्ते में कम से कम 2 बार यह प्रक्रिया अपनाएं ताकि आपके बालों को भरपूर पोषण मिले और वे स्वस्थ बने रहें। इसके अलावा तेल मालिश से बालों की नमी भी बनी रहती है।

गर्म पानी से धोने से बचें

गर्म पानी से बाल धोने से उनकी नमी खो जाती है और वे रूखे हो जाते हैं।

हमेशा गुनगुने पानी का उपयोग करें, जो बालों की प्राकृतिक नमी को बनाए रखता है। गुनगुने पानी से बाल धोने से वे मुलायम और चमकदार दिखते हैं।

इसके अलावा गुनगुने पानी से सिर का खून का दौरा भी बेहतर होता है, जिससे बालों की जड़ें मजबूत होती हैं। इस तरह आपके बाल स्वस्थ और सुंदर बने रहते हैं।

बालों के लिए कंडीशनर का इस्तेमाल करें

बालों को नरम बनाने में मदद करता है और उन्हें उलझन से बचाता है। शैंपू करने के बाद हमेशा कंडीशनर लगाएं ताकि आपके बाल मुलायम रहें।

इसके लिए आप बाजार में उपलब्ध प्राकृतिक सामग्री वाले कंडीशनर का उपयोग कर सकती हैं या फिर घर पर ही बनाकर इस्तेमाल कर सकती हैं।

इसके अलावा कंडीशनर लगाने से बालों की चमक भी बढ़ती है और वे टूटने से बचते हैं।

गर्मी वाले उपकरणों का कम करें उपयोग

स्ट्रेटनर या कर्लर जैसे उपकरण का ज्यादा उपयोग करने से बाल कमजोर हो जाते हैं और टूटने लगते हैं।

अगर आपको इन्हें इस्तेमाल करना ही है तो पहले अपने बालों पर हीट प्रोटेक्टिव स्प्रे लगाएं ताकि नुकसान कम हो सके।

इसके अलावा गर्मी के बाद बालों को ठंडे हवा से सुखाएं, जिससे उनकी नमी बनी रहेगी। कभी-कभी बिना गर्मी के भी नए लुक आजमाएं, जैसे कि चोटी या बन।

सही आहार लें

आपका आहार आपके बालों की सेहत पर सीधा असर डालता है। विटामिन-ए, विटामिन-बी, विटामिन-सी, विटामिन-डी, विटामिन-ई, आयरन, जिंक आदि पोषक तत्वों से भरपूर आहार लें ताकि आपके बाल मजबूत बने रहें।

हरी सब्जियां, फल, नट्स और दूध आदि चीजें अपने आहार में शामिल करें।

इन सरल तरीकों को अपनाकर आप भी अपने बालों की देखभाल कर सकती हैं और उन्हें टूटने से बचा सकती हैं।

खास-खबर

टटेंगा-भरदा-मोहंदीपाट मार्ग का निर्माण प्रगति पर, ग्रामीणों को मिलेगी बेहतर सुविधा



बालोद। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क को मजबूत बनाने और आवागमन की सुविधा बेहतर करने के लिए सड़क निर्माण कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। इसी कड़ी में गुण्डरदेही विकासखंड के अंतर्गत टटेंगा-भरदा-मोहंदीपाट मार्ग का निर्माण कार्य प्रगति पर है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मंशानुरूप तथा उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण विभाग मंत्री अरुण साव के नेतृत्व में ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सड़क सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा के निर्देशानुसार जिले में सड़क निर्माण एवं बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मूलभूत न्यूनतम सेवा के अंतर्गत टटेंगा-भरदा-मोहंदीपाट मार्ग के किलोमीटर 1/2 से 4/4 तक कुल 3.40 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए 450.86 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इस कार्य के लिए अनुबंध एवं कार्यादेश जारी किया जा चुका है तथा निर्माण कार्य प्रगति पर है। इस मार्ग के निर्माण से टटेंगा, भरदा और मोहंदीपाट सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। ग्रामीणों का रोजमर्रा का सफर आसान होगा तथा किसानों को अपनी कृषि उपज बाजार और मंडियों तक पहुंचाने में सहूलियत होगी।

दूरस्थ अंचलों के हर गांव तक विकास और बुनियादी सुविधाएं पहुंचाना हमारी प्राथमिकता : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री साय ने जोकारी में 29.32 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का किया लोकार्पण एवं भूमिपूजन

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि प्रदेश के दूरस्थ वनांचलों और अंतिम छोर पर बसे गांवों तक विकास का लाभ पहुंचाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सड़क, बिजली, पेयजल और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विस्तार से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। हमारी सरकार का संकल्प है कि विकास की मुख्यधारा से कोई गांव और कोई परिवार वंचित न रहे। मुख्यमंत्री साय जशपुर जिले के कुनकुरी विकासखंड अंतर्गत ग्राम जोकारी में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने लोक निर्माण विभाग एवं सेतु विभाग के अंतर्गत 29 करोड़ 32 लाख 84 हजार रुपये की लागत के पांच विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन कर क्षेत्रवासियों को महत्वपूर्ण सौगात दी। इनमें 6 करोड़ 55 लाख 53 हजार रुपये की लागत के एक कार्य का लोकार्पण तथा 22 करोड़ 77 लाख 31 हजार रुपये की लागत के चार कार्यों का भूमिपूजन शामिल है।



मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास को विशेष प्राथमिकता दे रही है। दूरस्थ गांवों में बेहतर सड़क संपर्क और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति से न केवल लोगों का दैनिक जीवन सुगम होगा, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और रोजगार के क्षेत्र में भी नए अवसर उपलब्ध होंगे।

मुख्यमंत्री साय ने कार्यक्रम में विद्युत विभाग के अंतर्गत ग्राम काईकछार एवं बालाछापर में कुल 4 करोड़ 45 लाख रुपये की लागत से निर्मित दो 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्रों का लोकार्पण किया। इन उपकेंद्रों के प्रारंभ होने से क्षेत्र के 19 गांवों में बिजली आपूर्ति व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। काईकछार विद्युत उपकेंद्र से काईकछार, चांपा टोली, रामबंध, बरपानी, ढारेन, जामपानी, सालामाली, केंदपानी और टेढ़ा पहाड़ सहित 9 गांवों के उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। इसी प्रकार बालाछापर विद्युत उपकेंद्र से बालाछापर, पुरनानगर, सिटेंगा, कनमोरा, रेंगोला, रायकोना, जबला, जोगीमारा, बढ़ईखाना और रजौटी सहित 10 गांवों में विद्युत आपूर्ति बेहतर होगी।

इन दोनों उपकेंद्रों के संचालन से क्षेत्र में विद्युत वितरण व्यवस्था अधिक सुदृढ़ होगी तथा ग्रामीण उपभोक्ताओं को निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इससे घरेलू उपभोक्ताओं के साथ कृषि एवं अन्य ग्रामीण गतिविधियों को भी लाभ मिलेगा।

सामाजिक भवन, महतारी सदन और खेल सुविधाओं की मिली सौगात

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने क्षेत्रवासियों की मांग पर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं। उन्होंने ग्राम बनकम्बो में चीक समाज के लिए 50 लाख रुपये की लागत से सामाजिक भवन निर्माण की घोषणा की। इस भवन से समाज के लोगों को सामाजिक, सांस्कृतिक एवं सामुदायिक आयोजनों के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री ने ग्राम जोकारी में 30 लाख रुपये की लागत से महतारी सदन निर्माण की घोषणा की। महतारी सदन महिलाओं की सामूहिक गतिविधियों, बैठकों और सामाजिक सहभागिता के लिए महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जोकारी में मिनी स्टेडियम एवं खेल मैदान निर्माण की घोषणा करते हुए क्षेत्र के युवाओं को खेलकूद के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में खेल सुविधाओं का विस्तार युवाओं की प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है। खेल मैदान और मिनी स्टेडियम से स्थानीय युवाओं को अपनी प्रतिभा निखारने तथा विभिन्न खेल गतिविधियों में भाग लेने के बेहतर अवसर मिलेंगे।

गांवों की समृद्धि से ही सशक्त और विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार गांवों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। अधोसंरचना निर्माण के साथ सामाजिक सुविधाओं का विस्तार, महिलाओं का सशक्तिकरण और युवाओं को बेहतर अवसर उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि जोकारी और आसपास के गांवों को मिली इन विकास कार्यों की सौगात से क्षेत्र की प्रगति को नई गति मिलेगी। सरकार का प्रयास है कि प्रदेश के प्रत्येक गांव में विकास की सुविधाएं पहुंचें और ग्रामीणों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों की खुशहाली और समृद्धि ही विकसित छत्तीसगढ़ की मजबूत नींव है। इसी संकल्प के साथ राज्य सरकार प्रदेश के हर क्षेत्र में विकास कार्यों को निरंतर आगे बढ़ा रही है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा सुरक्षित बचपन अभियान के तहत जिला पंचायत में एक दिवसीय प्रशिक्षण एवं कार्यशाला

श्रीकंचनपथ न्यूज

बालोद। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन एवं प्रचार प्रसार हेतु तथा छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर द्वारा जारी प्लान आफ एक्शन के अन्तर्गत श्याम लाल नवरत्न, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालोद के आदेशानुसार 27 नवंबर को जिला पंचायत बालोद में सुश्री भारती कुलदीप, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालोद के द्वारा सुरक्षित बचपन अभियान के अंतर्गत एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया।



बच्चों की सुरक्षा, उनके अधिकारों के संरक्षण तथा बाल अपराधों की रोकथाम के प्रति समाज में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में जिले के विभिन्न शासकीय एवं अर्धशासकीय विद्यालयों से बड़ी संख्या में शिक्षक एवं शिक्षिकाएं उपस्थित हुए। कार्यशाला के दौरान संस्था द्वारा संचालित सुरक्षित बचपन अभियान के उद्देश्यों, गतिविधियों एवं महत्व के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। साथ ही अभियान का प्रचार-प्रसार करते हुए अधिक से अधिक लोगों को बच्चों की सुरक्षा एवं उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने पर जोर दिया गया। इस अवसर पर बच्चों के साथ होने वाले लैंगिक अपराध, बाल शोषण बाल श्रम, बाल विवाह, बाल तस्करी एवं अन्य प्रकार की हिंसा और दुर्व्यवहार जैसे गंभीर विषयों पर चर्चा की गई। शिक्षकों को बताया गया कि विद्यालय बच्चों के लिए शिक्षा का केंद्र होने के साथ-साथ उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण का भी महत्वपूर्ण स्थान है।

ऐसे में शिक्षक बच्चों के व्यवहार में होने वाले असामान्य बदलावों को समझकर समय रहते उनकी सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। साथ ही शिक्षकों को प्रेरित किया गया कि वे विद्यार्थियों को गुड टच बैड टच, व्यक्तिगत सुरक्षा, बाल अधिकारों एवं अपने विरुद्ध होने वाले अपराधो के प्रति जागरूक करें।

रौतिया समाज की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं का संरक्षण प्राथमिकता

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। छत्तीसगढ़ की समृद्ध जनजातीय संस्कृति, लोकपरंपराएं और सामाजिक एकजुटता हमारी सबसे बड़ी धरोहर हैं। रौतिया समाज ने अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान, रीति-रिवाजों और परंपराओं को पीढ़ी-दर-पीढ़ी सहेजकर रखा है। हमारी सरकार समाज की इस गौरवशाली विरासत के संरक्षण और संवर्धन के साथ सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री साय ने जशपुर जिले के कुनकुरी विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत कंडोरा में आयोजित सोहराई करमा महोत्सव को संबोधित करते हुए यह बात कही। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री घोषणा मद से 50-50 लाख रुपये की लागत से निर्मित अखिल भारतीय रौतिया समाज भवन एवं अखरा विकास कार्यों का लोकार्पण कर समाज को एक करोड़ रुपये के विकास कार्यों की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने समाज की मांग पर सामाजिक भवन परिसर में स्थायी मंच एवं बाउंड्रीवॉल निर्माण की भी घोषणा की। महोत्सव में पहुंचने पर रौतिया समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री साय का पारंपरिक करमा नृत्य, तिलक-चंदन और गजमाला से आत्मीय स्वागत किया। पारंपरिक वेशभूषा में सजे कलाकारों की मनमोहक प्रस्तुतियों ने पूरे वातावरण को लोकसंस्कृति के रंगों से सराबोर कर दिया।



मुख्यमंत्री श्री साय ने सोहराई करमा महोत्सव एवं नवनिर्मित समाज भवन के लोकार्पण पर समाज के सभी लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दीं।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे निर्मित यह भव्य सामाजिक भवन समाज की एकता, संगठन और रचनात्मक गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। यहां सामाजिक एवं सांस्कृतिक आयोजनों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। साथ ही नई पीढ़ी को अपनी जड़ों, संस्कारों और गौरवशाली परंपराओं से जोड़ने का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि रौतिया समाज ने अपनी सांस्कृतिक पहचान को जीवंत रखते हुए सनातन संस्कृति और सामाजिक मूल्यों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

समाज की एकजुटता और परंपराओं के प्रति समर्पण अनुकरणीय है। उन्होंने समाज के लोगों से शिक्षा पर विशेष ध्यान देने और नई पीढ़ी को आधुनिक अवसरों से जोड़ते हुए अपनी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने का आह्वान किया।मुख्यमंत्री साय ने कहा कि आगामी 13 दिसंबर को राज्य सरकार के तीन वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इन तीन वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटियों को पूरा करने और प्रदेश के हर वर्ग के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए निरंतर कार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए संचालित महतारी वंदन योजना प्रदेश की लाखों माताओं-बहनों के जीवन में खुशहाली ला रही है।

किसानों की सुविधा के लिए 360 नए धान खरीदी केंद्र

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की मेहनत का पूरा सम्मान करते हुए उनके हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। किसानों को धान बेचने में किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए प्रदेश में 360 नए धान उपार्जन केंद्र प्रारंभ किए गए हैं। खरीदी केंद्रों में आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल तक धान खरीदी की व्यवस्था की गई है। किसानों को धान खरीदी के अंतर की राशि भी उनके खातों में अंतरित की जाएगी। सरकार का प्रयास है कि अन्नदाताओं को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले और खेती-किसानी अधिक लाभकारी बने।

एचआईवी की रोकथाम के लिए व्यापक जनजागरूकता जरूरी : स्वास्थ्य मंत्री

समारोह में 2 सुरक्षित और 13 सक्षम जिलों के स्वास्थ्य अधिकारी सम्मानित

श्रीकंचनपथ न्यूज

मनेंद्रगढ़। छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की अध्यक्षता में मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में राज्य स्तरीय विश्व एड्स दिवस समारोह का आयोजन किया गया। परियोजना संचालक संजीव झा व अतिरिक्त परियोजना संचालक डॉ खेमराज सोनवानी के मार्गदर्शन में आयोजित कार्यक्रम में एचआईवी/एड्स की रोकथाम, जागरूकता, जांच एवं उपचार के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 15 जिलों के स्वास्थ्य अधिकारियों को सम्मानित किया गया।

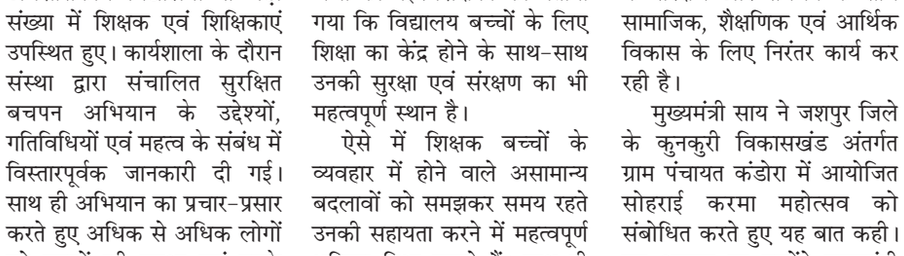

समारोह के दौरान मिशन एड्स सुरक्षा अभियान के अंतर्गत निर्धारित मापदंडों के आधार पर 2 सुरक्षित जिलो मोहला मानपुर व सरगुजा सहित 13 सक्षम जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी , जिला एड्स नियंत्रण अधिकारी व जिला कार्यक्रम प्रबंधक को सम्मानित किया गया। यह सम्मान जिला स्तर पर एचआईवी/एड्स नियंत्रण कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन, स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने तथा विभिन्न विभागों के समन्वय से किए गए प्रयासों के लिए दिया गया।

कार्यक्रम में योग आयोग के अध्यक्ष संजय अग्रवाल, भाजपा जिलाध्यक्ष चंपा देवी पावले, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष प्रतिमा यादव, उपाध्यक्ष धर्मेंद्र पटवा, मंडल अध्यक्ष रोहित वर्मा, बबिता सिंह एवं विधायक प्रतिनिधि महेंद्र पाल सिंह मौजूद रहे।

इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने कहा कि एचआईवी संक्रमण की रोकथाम के लिए व्यापक जनजागरूकता, समय पर जांच, संक्रमित व्यक्तियों की पहचान, व स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ने तथा उपचार की निरंतरता सुनिश्चित करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि एचआईवी के साथ जीवन जी रहे लोगों के प्रति भेदभाव और सामाजिक कलंक को समाप्त करने और उन्हें सम्मानजनक एवं समान अवसरों के साथ जीवन जीने का वातावरण उपलब्ध कराने के लिए समन्वित प्रयासों व जन जागरूकता की जरूरत है, उन्होंने एच आईवी एड्स की रोकथाम के लिए किए जा रहे विभागीय प्रयासों की सराहना की।

श्री जायसवाल ने कहा कि विश्व एड्स दिवस का आयोजन समाज में एचआईवी/एड्स के प्रति जागरूकता बढ़ाने, संक्रमण की रोकथाम के लिए सामूहिक प्रयासों को मजबूत करने और प्रभावित लोगों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने का महत्वपूर्ण अवसर है। इस अवसर पर योग आयोग के अध्यक्ष संजय अग्रवाल द्वारा स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव पर एचआईवी के साथ जीवन जी रहे लोगो को योग प्रशिक्षक के रूप में तैयार करने के साथ ही रोकथाम हेतु जनजागरण करने पर सहमति दी गई। उल्लेखनीय है कि इस पहल से एच आईवी संक्रमितों के जीवन में तनाव कम करने व प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी होगी।

इस अवसर छत्तीसगढ़ राज्य एड्स नियंत्रण समिति के अतिरिक्त परियोजना संचालक डॉ खेमराज सोनवानी, संयुक्त संचालक आईईसी डॉ. भाग्यश्री वर्मा, डिप्टी डायरेक्टर टीआई विक्रांत वर्मा सहित छत्तीसगढ़ राज्य एड्स नियंत्रण समिति के अधिकारी सहित विभिन्न जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के जिला कार्यक्रम प्रबंधक व बड़ी संख्या में आम लोगों की सहभागिता रही।

धान खरीदी में जिले की निरंतर बढ़त

बालोद। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के अंतर्गत समर्थन मूल्य पर चल रही धान खरीदी में बालोद जिला निरंतर उल्लेखनीय प्रगति दर्ज कर रहा है। कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा के कुशल नेतृत्व, सतत निगरानी और बेहतर प्रशासनिक प्रबंधन के परिणामस्वरूप जिले के सभी 161 धान उपार्जन केंद्रों में खरीदी कार्य सुचारू एवं व्यवस्थित रूप से संचालित हो रहा है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, 26 नवंबर की स्थिति में जिले में कुल 10,671 किसानों से 38,299.60 मीट्रिक टन धान का उपार्जन किया जा चुका है। खाद्य एवं सहकारिता विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, 26 नवंबर तक जिले में उपार्जित कुल 38,299.60 मीट्रिक टन धान में 29,088.32 मीट्रिक टन पतला, 1,746.56 मीट्रिक टन सरना धान शामिल है।

CAR DECOR
House Of Exclusive Seat Cover, Car Stereos Matting & Sun Control Film & Other Accessories
Shop No.3 Nafish Tower. Opp. Indian Coffee House, Akashganga, Bhilai
Mo.9300771925, 0788-4030919
K. Satyanarayan

ॐ SAIRAM Mobile Accessories
मोबाईल शॉप में कार्य करने हेतु लड़को की आवश्यकता है
7000415602
Shop No. 78, Himalaya Complex, Supela, Bhilai

ROCKEY INDUSTRIES FURNITURE PALACE
Deals in: (Steel & Wooden) Luxury & Imported Furniture
Akash Ganga, Supela, Bhilai Ph. 2296430

चौरसिया ज्वेलर्स
आकर्षक सोने चांदी के आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता
बेन्टेक्स एवं ग्रहरत्न उपलब्ध यहां
उचित ब्याज दर पर गिरवी रखी जाती है
मुक्तिधाम रोड, रामनगर, सुपेला, भिलाई
9827938211, 9827171332

Jaquar Roca Parryware AJAY FLOWLINE
Shri Vijay Enterprises
Sanitarywares, Tiles, CPVC Pipes & Bathroom Fittings etc.
Supela Market, Bhilai
PH. 0788-4030909, 2295573

खास खबर

चलती ट्रेन में मोबाइल लूटने का प्रयास पड़ा भारी, हमले में यात्री की मौत

दुर्ग। खुर्सीपार थाना क्षेत्र में चलती ट्रेन में यात्री का मोबाइल लूटने के प्रयास और मारपीट के दौरान उसकी मौत के मामले में पुलिस ने दो विधि से संघर्षरत बालकों को अभिरक्षा में लिया है। ट्रेन क्रमांक 12856 में सफर कर रहे मोहम्मद फैजान उर्फ सोनू (25 वर्ष), का मोबाइल छीनने का प्रयास किया गया। इस दौरान एक बालक ने यात्री को थप्पड़ मारा, जबकि दूसरे ने डंडे से वार कर दिया। हमले के कारण यात्री मोबाइल सहित चलती ट्रेन से नीचे गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे उपचार के लिए सुपेला अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों बालक रेलवे ट्रैक के किनारे खड़े होकर गुजरती ट्रेनों में खिड़की के पास बैठे यात्रियों को निशाना बनाते थे और उनके मोबाइल छीनने का प्रयास करते थे। इसी दौरान किए गए हमले में यात्री की जान चली गई। पुलिस ने मामले में अपराध क्रमांक 0542/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1), 309(4), 309(6) एवं 3(5) के तहत अपराध दर्ज किया है। किशोर न्याय संबंधी प्रावधानों के चलते बालकों की पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है। मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है।

कत्लखाने ले जाए जा रहे 16 मवेशियों से भरा वाहन पकड़ा दो आरोपी गिरफ्तार

दुर्ग। रायपुर से नागपुर कत्लखाने ले जाए जा रहे 16 मवेशियों से भरे आयशर वाहन को दुर्ग जिले की कुम्हारी पुलिस ने पकड़ा है। वाहन में 12 गाय और 4 बछड़ों को ठूंस-ठूंसकर अमानवीय तरीके से भरा गया था। पुलिस ने वाहन चालक और परिचालक को गिरफ्तार कर मवेशियों सहित करीब 3 लाख 90 हजार रुपये की संपत्ति जब्त की है। पुलिस के मुताबिक, थाना कुम्हारी को मुखबिर से सूचना मिली थी कि आयशर वाहन में मवेशियों को भरकर रायपुर की ओर से नागपुर स्थित कत्लखाने ले जाया जा रहा है। जांच के दौरान वाहन में 12 गाय, 3 काले बछड़े और एक अन्य बछड़ा सहित कुल 16 मवेशी मिले। सभी को वाहन में ठूंस-ठूंसकर भरा गया था। मवेशियों के परिवहन से संबंधित वैध दस्तावेज मांगने पर चालक और परिचालक कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। पुलिस ने वाहन चालक अकबर पाशा (33 वर्ष) निवासी काकिया मोहल्ला, कोलार और परिचालक तबरेज पाशा (37 वर्ष) निवासी बीडी कॉलोनी, जिला कोलार, कर्नाटक को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ थाना कुम्हारी में अपराध क्रमांक 389/2026 के तहत छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 6 और 10, पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11(1) तथा मोटरयान अधिनियम की धारा 66/192 के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस ने आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।

फर्जी ऋण पुस्तिका तैयार कर एक ही जमीन कई लोगों को बेची, शातिर आरोपी गिरफ्तार

जमीन की रजिस्ट्री एवं पावर ऑफ अटॉर्नी के नाम पर कई लोगों को बनाया शिकार

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। दुर्ग जिले के ग्राम अरसी की एक ही जमीन के अलग-अलग ऋण पुस्तिका तैयार कर कई लोगों को पावर ऑफअटॉर्नी देकर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया। प्रार्थी से जमीन का सौदा 300000 रुपये में तय कर ऑनलाइन, बैंक खाते एवं नगद के माध्यम से राशि प्राप्त की गई थी। आरोपी द्वारा दस्तावेजों में त्रुटि सुधारकर रजिस्ट्री कराने का आश्वासन देकर प्रार्थी को पावर ऑफ अटॉर्नी दी गई थी। इस मामले में धारा 318(4) बीएनएस के अपराध दर्ज किया गया और फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है।



इस मामले में मिली शिकायत के अनुसार ग्राम अरसी स्थित खसरा नंबर 1051 एवं 1086, प्रत्येक का रकबा 0.16 हेक्टेयर, कुल 0.32 हेक्टेयर भूमि का सौदा के दीपक देशलहरे साथ 300000 रुपये में तय हुआ था। उक्त राशि प्रार्थी द्वारा ऑनलाइन, बैंक खाते एवं नगद माध्यम से दीपक देशलहरे को दी गई थी। दीपक देशलहरे द्वारा दस्तावेजों में त्रुटि होने की बात कहकर उन्हें सुधारने एवं रजिस्ट्री कराने का आश्वासन दिया गया। इस दौरान दीपक देशलहरे ने प्रार्थी को पावर ऑफ अटॉर्नी प्रदान की, जिसके माध्यम से प्रार्थी स्वयं अथवा किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर रजिस्ट्री करा सकता था।

लगभग 11 माह बाद प्रार्थी को जानकारी मिली कि दीपक देशलहरे ने उसी भूमि के संबंध में अन्य व्यक्ति के नाम पर भी पावर ऑफ अटॉर्नी देकर रजिस्ट्री करा दी है। तहसील कार्यालय से जानकारी लेने पर उक्त भूमि के नामांतरण संबंधी प्रक्रिया में कई व्यक्तियों द्वारा आपत्ति प्रस्तुत किया जाना सामने आया। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना बोरी में अपराध क्रमांक 32/2026 धारा 318(4) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना के दौरान दीपक देशलहरे के फरार होने पर थाना बोरी पुलिस द्वारा लगातार पतासाजी की गई। आरोपी की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम गठित कर संभावित ठिकानों पर तलाश एवं दबिश दी गई। पुलिस टीम के प्रयासों से दीपक देशलहरे को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ एवं अपराध में संलिप्तता के आधार पर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आरोपी दीपक देशलहरे द्वारा एक ही भूमि के संबंध में अलग-अलग ऋण पुस्तिका तैयार कर तथा दस्तावेजों में त्रुटि सुधारने एवं रजिस्ट्री कराने का आश्वासन देकर लोगों से रकम प्राप्त की जाती थी। इसके बाद उसी भूमि के संबंध में अलग-अलग व्यक्तियों को पावर ऑफ अटॉर्नी देकर रजिस्ट्री की प्रक्रिया कराई जाती थी, जिससे एक ही भूमि को लेकर कई व्यक्तियों के बीच विवाद एवं आर्थिक धोखाधड़ी की स्थिति उत्पन्न हुई।

उक्त कार्यवाही में थाना बोरी के सउनि तानसिंह सोनवानी, आरक्षक क्रमांक 487 ऋषि बंछोर, आरक्षक क्रमांक 112 संजीव सोनी, आरक्षक क्रमांक 707 जितेन्द्र धीवर एवं आरक्षक क्रमांक 1120 प्रशांत साहू की महत्वपूर्ण भूमिका रही। दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि किसी भी भूमि का क्रय-विक्रय करने से पूर्व संबंधित भूमि के मूल दस्तावेज, ऋण पुस्तिका, खसरा, बी-1, नामांतरण की स्थिति एवं स्वामित्व का राजस्व विभाग से विधिवत सत्यापन अवश्य कराएं। केवल पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर भूमि का सौदा करने से पहले सभी कानूनी पहलुओं की जांच करें। किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी की जानकारी मिलने पर तत्काल नजदीकी थाना अथवा पुलिस को सूचित करें।

बाइक की टक्कर से बुजुर्ग की मौत, दो मासूम हादसे में घायल

श्रीकंचनपथ न्यूज

जांजगीर। सड़क हादसों ने दो परिवारों की खुशियां छीन लीं। 28 नवंबर की सुबह पेट्रोल भरवाकर घर लौट रहे बुजुर्ग की सड़क दुर्घटना में जान चली गई तो कहीं रोजी-रोटी की तलाश में दूसरे प्रदेश गए 30 वर्षीय युवक की मौत ने दो मासूम बच्चों को बेसहारा कर दिया।

दोनों घटनाओं ने परिवारों को गहरे सदमे में डाल दिया है। पहली घटना में छपोरा चौकी अंतर्गत ग्राम अमलीडीह की तरफ हुई। यहां तेज रफ्तार बजाज प्लेटिना बाइक चालक ने पेट्रोल पंप से निकल रहे हरिसिंह चंद्रा (70-75 वर्ष) को टक्कर मार दी। हरिसिंह मरघट्टी से भुतहा की ओर जा रहे थे। हादसा सुबह करीब 10.30 बजे हुआ। टक्कर इतनी जोरदार थी कि हरिसिंह



के सिर में गंभीर चोट आई और उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलने पर छपोरा चौकी प्रभारी संतोष तिवारी स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने लोगों को समझाइश दी और मृतक के परिजनों को तत्काल 25 हजार रुपए की सहायता राशि दिलाई। शव को पोस्टमार्टम के लिए मालखरौदा अस्पताल भेजा गया है। बाइक चालक घनश्याम देवांगन निवासी कुर्दा, चांपा के खिलाफ तेज और लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने की बात सामने आई है।

जिले में सप्ताह भर में 10 से अधिक सड़क हादसे हो चुके हैं। दो दिन पहले हुई दो अलग-अलग दुर्घटनाओं में चार लोग घायल हो गए, जिनमें तीन नाबालिग लड़कों की हालत गंभीर बनी हुई है। जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद तीनों को बिलासपुर रेफर कर दिया गया, जबकि दूसरे हादसे में स्कूटी की टक्कर से एक युवक का पैर टूट गया। खोखसा ओवरब्रिज में दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत हो गई थी। बाइक पर सवार सत्यप्रकाश श्रीवास, समीर देवांगन दोस्त की जन्मदिन पार्टी से लौट रहे थे। तुम्मा दूसरी घटना ने ग्राम पंचायत तुम्मा के आमापारा मोहल्ले के एक परिवार को कभी न भरने वाला जख्म दे दिया।

यहां के निवासी महादेव साहू (30 वर्ष) की राजस्थान के जयपुर में सड़क हादसे में मौत हो गई। उनके दो मासूम बच्चों ने महज दो महीने के भीतर पहले मां और अब पिता को खो दिया। पत्नी के दशकर्म के बाद महादेव परिवार के साथ रोजी-रोटी कमाने जयपुर चले गए थे। बताया जा रहा है कि घटना के दिन शाम को महादेव सब्जी खरीदने जा रहे थे। इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार में आई कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी।

पेट्रोल पंप मोड़ के पास सुरक्षा का अभाव पेट्रोल पंप मोड़ के पास सुरक्षा व्यवस्था नहीं होने से पांच किलोमीटर के दायरे में सड़क खतरनाक हो गई है। यहां न तो सही कट और स्पीड ब्रेकर बने हैं, और न ही पंप के एंट्री-एग्जिट की समुचित व्यवस्था है। इसी लापरवाही और अव्यवस्था के कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं।

युवक ने मां और पड़ोसी महिला पर किया धारदार हथियार से हमला

श्रीकंचनपथ न्यूज

धमतरी। धमतरी शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत टिकरा पारा वार्ड में एक सनकी युवक ने घर में मां पर धारदार हथियार से हमला किया। मां पर हमला करने के बाद आरोपी हाथ में हथियार लेकर सीधे घर से बाहर निकल आया। उसने पास ही छोटी सी दुकान चलाने वाली कौशल्या बाई पर अचानक हमला बोल दिया।

आरोपी के धारदार हथियार से हमले में कौशल्या बाई का हाथ बुरी तरह कट गया और वे मौके पर ही गिर पड़ीं। घायल महिला को फौरन इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।

इस गंभीर वारदात की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस तुरंत पूरी तरह हरकत में आ गई। पुलिस टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर इलाके की पूरी घेराबंदी की और आरोपी देवा निर्मलकर को हिरासत में ले लिया। पुलिस हिरासत में उससे बहुत सख्ती से पूछताछ की जा रही है। युवक ने किस वजह और गुस्से में आकर मां और पड़ोसी बुजुर्ग महिला पर जानलेवा हमला किया, इसकी असली वजह पुलिस की जांच पूरी होने के बाद ही सामने आ पाएगी।

दिव्यांग नाबालिग से बार-बार दुष्कर्म करने वाले जीजा को 20 साल की सजा, पांच लाख मुआवजे का आदेश

श्रीकंचनपथ न्यूज

दुर्ग। दुर्ग में विशेष पॉक्सो अदालत ने 13 वर्ष की मानसिक रूप से दिव्यांग नाबालिग से कई बार दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी जीजा को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश और चतुर्थ एफटीएससी विशेष न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अनिष दुबे की अदालत ने आरोपी पर एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न देने पर दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना पड़ेगा। इसके साथ ही, अदालत ने शासन की पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना के तहत पीड़िता को 5 लाख रुपये की राशि देने का आदेश दिया है।

यह मामला नेवई थाना क्षेत्र का है। रायपुर जिले के अभनपुर क्षेत्र स्थित ग्राम परसदा का



निवासी 30 वर्षीय तुकाराम निषाद उर्फ राजा निषाद दुर्ग में किराए का मकान लेकर पीड़िता के घर के पड़ोस में रहता था। आरोपी का बच्चा और पीड़िता साथ खेलते थे, इसलिए नाबालिग का उसके घर आना-जाना रहता था। आरोपी ने 20 फरवरी से 18 अप्रैल के बीच बालिका के साथ कई बार दुष्कर्म किया। घटना का पता चलने पर पीड़िता की मां ने 23 अप्रैल को नेवई थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने उसी दिन आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और वह 24 अप्रैल से न्यायिक हिरासत में है।

अदालत में पीड़िता की उम्र साबित करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र तथा स्कूल के दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। इनमें दर्ज जन्मतिथि के आधार पर कोर्ट ने माना कि अपराध के समय बच्ची की आयु 13 वर्ष थी। मानसिक रूप से दिव्यांग पीड़िता ने सुनवाई के दौरान इशारों तथा आसान शब्दों में अपनी बात रखी। चिकित्सीय जांच में गंभीर चोट न होने के बावजूद अदालत ने कहा कि इससे पीड़िता का बयान झूठा नहीं ठहरता। विशेष न्यायालय ने आरोपी को पॉक्सो अधिनियम की धारा 5(ट), 5(ठ) और धारा 6 के तहत दोषी करार दिया।

करंट लगने से नर हाथी की मौत, शिकारी गिरफ्तार

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायगढ़। रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ वन मंडल के बरतापाली में करंट लगने से एक नर हाथी की मौत हो गई। वन विभाग की जांच में सामने आया कि जंगली सूअर का शिकार करने के लिए खेत में करंट प्रवाहित तार लगाया गया था। इसकी चपेट में आने से हाथी की जान चली गई। मामले में वन विभाग ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

धरमजयगढ़ रेंज के ग्राम बरतापाली के कक्ष क्रमांक 437 में एक नर हाथी का शव मिला था। इसकी सूचना मिलने के बाद वन विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। स्निफर डॉग की मदद से जांच की गई। इसमें पता चला कि जंगली सूअर



के शिकार के लिए खेत में करंट प्रवाहित तार लगाया गया था। जांच के दौरान वन विभाग ने अजय भगत (38), जयानंद भगत (37), भगवानों भगत (50) और रामदयाल (38) को हिरासत में लिया। सभी आरोपी नयागांव के निवासी बताए गए हैं। पूछताछ में आरोपियों ने शिकार के लिए करंट प्रवाहित तार लगाने की बात स्वीकार की।

वन विभाग ने चारों आरोपियों के खिलाफ वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम की धाराओं के तहत कार्रवाई की है। आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जाएगा। मामले में आगे की जांच और कार्रवाई जारी है।

ऑनलाइन सट्टा खेलते आदतन सटोरिया गिरफ्तार, लाखों के लेन-देन का खुलासा

श्रीकंचनपथ न्यूज

कोरबा। कोरबा जिले के कोतवाली पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने पुरानी बस्ती रानी रोड स्थित मस्जिद के पीछे दबिश दी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आदतन सटोरिया मोह. इसाक कुरैशी उर्फ निक्की को गिरफ्तार किया है।

आरोपी मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन सट्टा खेलता और खिलाता पकड़ा गया। यह कार्रवाई 28 नवंबर 2026 को की गई। आरोपी मोबाइल पर श्रीदेवी, टाइम बाजार, मिलन डे और कल्याण जैसी साइटों का उपयोग कर रहा था। वह विभिन्न अंकों और जोड़ियों पर सट्टा खेल रहा था। मौके पर आरोपी सट्टा पट्टी लिखते हुए भी मिला।

जब्ती और जांच

पुलिस ने आरोपी के कब्जे से सट्टा पट्टी, मोबाइल और नकद रकम जब्त की है। मोबाइल की जांच करने पर साइटों के स्क्रीनशॉट और अंकों के फोटो मिले। जांच में फोन-पे नंबर से लाखों रुपये के ऑनलाइन यूपीआई लेन-देन की जानकारी सामने आई है। पुलिस अब उसके लेन-देन और नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है।



आरोपी की उम्र 43 वर्ष है। वह वार्ड क्रमांक 06, पुरानी रानी रोड दुर्गा मंदिर के पास का निवासी है। उसके पिता का नाम स्व. ईस्माइल कुरैशी है। उसके विरुद्ध थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 968/2026 दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धारा 6(क) के तहत की गई है।

पुलिस की अपील

पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे अवैध गतिविधियों से दूर रहें। इस प्रकार की जानकारी तत्काल नजदीकी थाना चौकी या डायल 112 पर दें। अवैध गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। कुछ दिन पहले ही बस स्टैंड क्षेत्र से छह से अधिक लोगों को पकड़ा गया था। उनके कब्जे से भी मोबाइल और सट्टा पट्टी बरामद हुई थी।

अवैध धान पर प्रशासन की लगातार कार्रवाई, 32 प्रकरणों में 7651 बोरी धान जब्त

कापू में गोदाम से 70 बोरी और पटेलपाली में ट्रक से 550 बोरी धान पकड़ा गया, जांच अभियान जारी

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायगढ़। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत समर्थन मूल्य पर धान खरीदी व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने तथा अवैध धान के भंडारण, परिवहन और अनियमित खरीदी-बिक्री पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार निगरानी और कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी के निर्देशानुसार राजस्व, खाद्य एवं मंडी विभाग की संयुक्त टीमें जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जांच कर रही हैं। इसी क्रम में 27 और 28 नवंबर को अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से भंडारित एवं परिवहन किए जा रहे धान को जब्त किया गया।



27 नवंबर को विकासखंड धरमजयगढ़ के ग्राम पंचायत कापू में खाद्य एवं राजस्व विभाग के संयुक्त दल ने राजू निराला के गोदाम की जांच की। इस दौरान गोदाम में अवैध रूप से भंडारित 70 बोरी धान पाया गया, जिसका कुल वजन 28 क्विंटल है। संयुक्त दल द्वारा धान की जब्ती कर आवश्यक कार्रवाई की गई। वहीं, 28 नवंबर को रायगढ़ तहसील के ग्राम पटेलपाली में ट्रक के माध्यम से धान का अवैध परिवहन किए जाने का मामला सामने आया। सूचना मिलने पर राजस्व एवं मंडी विभाग की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। जांच के दौरान ट्रक में 550 बोरी धान का अवैध रूप से परिवहन किया जाना पाया गया। टीम द्वारा धान को जब्त कर आवश्यक कार्रवाई की गई।

जिले में अवैध धान के भंडारण एवं परिवहन के विरुद्ध 28 नवंबर 2026 तक कुल 32 प्रकरणों में 7651 बोरी धान जब्त किया जा चुका है। 27 नवंबर तक जिले में 31 प्रकरणों में 7101 बोरी धान जब्त किया गया था, जिसका कुल वजन 2840.40 क्विंटल है। वहीं, 28 नवंबर को रायगढ़ तहसील के ग्राम पटेलपाली में ट्रक से 550 बोरी धान की अतिरिक्त जब्ती की गई। इसके साथ ही प्रकरणों की संख्या बढ़कर 32 और जब्त धान की मात्रा 7651 बोरी हो गई है। जिला प्रशासन द्वारा धान खरीदी केंद्रों के साथ-साथ गोदामों एवं परिवहन मार्गों पर भी निगरानी रखी जा रही है। राजस्व, खाद्य एवं मंडी विभाग के संयुक्त दलों द्वारा लगातार जांच की जा रही है, ताकि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी व्यवस्था में पारदर्शिता बनी रहे और अवैध गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध धान के भंडारण, परिवहन एवं खरीदी-बिक्री के मामलों में आगे भी जांच और कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।







छत्तीसगढ़ में जनगणना-2027 के द्वितीय चरण की तैयारियां तेज, फरवरी तक पूरा होगा जनसंख्या गणना का कार्य

मुख्य सचिव ने कलेक्टरों को समयबद्ध एवं त्रुटिरहित जनगणना के दिए निर्देश, 72 हजार से अधिक प्रगणक एवं पर्यवेक्षक संभालेंगे जिम्मेदारी

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। छत्तीसगढ़ में जनगणना-2027 के द्वितीय चरण के अंतर्गत जनसंख्या गणना की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इस चरण में प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति की जनसांख्यिकीय एवं सामाजिक-आर्थिक जानकारी संकलित की जाएगी। जनगणना के कार्य को समयबद्ध, त्रुटिरहित एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए यहां मंत्रालय महानदी भवन में मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में मुख्य सचिव ने सभी जिला कलेक्टरों, संभागायुक्तों एवं जिला जनगणना अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा में जनगणना का कार्य पूर्ण करने तथा मैदानी स्तर पर प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कार्यशाला में डिप्टी रजिस्ट्रार जनगणना ऑफइंडिया वृषाली वराडे, अपर मुख्य सचिव निहारिका बारिक, जनगणना निदेशक कार्तिकेय गोयल सहित प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टर, संभागायुक्त एवं विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।



भारत की जनगणना के डिप्टी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया श्रीमती वृषाली वराडे ने बताया कि जनगणना के प्रथम चरण में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य किया गया है, जबकि द्वितीय चरण में प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तिगत जनगणना की जाएगी। इसमें जनसांख्यिकीय एवं सामाजिक-आर्थिक जानकारियां संकलित की जाएंगी। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर देश एवं राज्यों की विकास योजनाओं और नीतियों का निर्माण किया जाता है। इसलिए जनगणना के आंकड़ों की विश्वसनीयता एवं शुद्धता अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जनगणना के लिए बड़ी संख्या में प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों की नियुक्ति तथा उनका गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण आवश्यक है। प्रगणकों को प्रत्येक व्यक्ति से निर्धारित प्रश्नों के माध्यम से जानकारी प्राप्त करनी होगी। इसमें प्रजनन, दिव्यांगता, धर्म एवं जाति जैसे महत्वपूर्ण विषयों से संबंधित प्रश्न भी शामिल हैं। उन्होंने जिला जनगणना अधिकारियों से सोशल मीडिया के माध्यम से जनजागरूकता बढ़ाने तथा जनगणना से संबंधित किसी भी प्रकार की भ्रामक जानकारी अथवा अफवाह का तत्काल खंडन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि शोधकर्ताओं सहित विभिन्न क्षेत्रों के लोग उच्च गुणवत्ता वाले जनगणना आंकड़ों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसे में आंकड़ों की विश्वसनीयता बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है।

मुख्य सचिव विकासशील ने कहा कि जनगणना का प्रथम चरण बेहतर ढंग से पूरा किया गया है। अब द्वितीय चरण को भी पूरी गंभीरता और समयबद्धता के साथ संपन्न करना है। उन्होंने कलेक्टरों को निर्देशित किया कि वे जनगणना संबंधी दिशा-निर्देशों का स्वयं भी अध्ययन करें और अपनी टीम को स्पष्ट जिम्मेदारियां सौंपें। उन्होंने कहा कि समय-सीमा का पालन, प्रगणकों का बेहतर प्रशिक्षण, पर्यवेक्षण एवं नियमित मॉनिटरिंग इस कार्य की सफलता के प्रमुख आधार हैं। प्रगणकों को नागरिकों एवं परिवारों से सहज संवाद स्थापित कर सही जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित किया जाए। नागरिकों की सहायता के लिए आवश्यक मार्गदर्शन एवं सहयोग व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए।

मुख्य सचिव ने जनगणना के दौरान नागरिकों के बीच किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति नहीं बनने देने पर जोर देते हुए कहा कि लोगों को स्पष्ट रूप से बताया जाए कि जनगणना में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल आंकड़ों का संकलन है। इसका किसी प्रकार के प्रमाण पत्र अथवा अन्य शासकीय पात्रता से संबंध नहीं है। उन्होंने जनगणना कार्य में संलग्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानांतरण पर रोक संबंधी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को भी कहा।

अपर मुख्य सचिव श्रीमती निहारिका बारिक ने कहा कि जनगणना के प्रति नागरिकों में विश्वास एवं सहयोग का वातावरण बनाना जरूरी है। इसके लिए प्रगणकों को प्रशिक्षित किया जाए कि वे परिवारों से किस प्रकार संवाद करें और आवश्यक जानकारी सहजता से प्राप्त करें। उन्होंने बस्तर के हाट-बाजारों सहित ग्रामीण एवं स्थानीय स्तर पर जनजागरूकता गतिविधियां आयोजित करने तथा लोगों को जनगणना की पूरी प्रक्रिया के बारे में सरल भाषा में जानकारी देने का सुझाव दिया।

प्रदेश के सभी 33 जिलों में होगी जनसंख्या गणना

जनगणना के द्वितीय चरण में प्रदेश के सभी 33 जिलों, 14 नगर पालिक निगमों, 19,978 गांवों एवं 195 नगरों में जनसंख्या गणना की जाएगी। इसके लिए 47 प्रमुख जनगणना अधिकारियों एवं 472 चार्ज के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था की गई है। प्रदेश में अनुमानित 60,682 गणना ब्लॉक बनाए जाएंगे। इनके लिए 10 प्रतिशत आरक्षित कर्मियों सहित कुल 62,102 प्रगणकों एवं 10,667 पर्यवेक्षकों की आवश्यकता होगी। लगभग छह प्रगणकों पर एक पर्यवेक्षक की व्यवस्था रहेगी।

प्रत्येक गणना ब्लॉक में लगभग 800 की जनसंख्या

प्रथम चरण में गठित मकान सूचीकरण ब्लॉकों को द्वितीय चरण में गणना ब्लॉकों में परिवर्तित किया जाएगा। प्रत्येक गणना ब्लॉक में लगभग 800 की जनसंख्या शामिल होगी। अधिक जनसंख्या वाले ब्लॉकों को आवश्यकतानुसार उप-गणना ब्लॉकों में विभाजित किया जाएगा। नए बसाहटों, झुग्गी बस्तियों, बहुमंजिला इमारतों तथा आवासीय एवं व्यावसायिक भवनों को भी गणना में शामिल किया जाएगा। मकान सूचीकरण ब्लॉकों की सीमाओं में विसंगतियों, क्षेत्रों के दोहराव एवं छूट गई बसाहटों का निराकरण 30 नवंबर 2026 तक करने के निर्देश दिए गए हैं।

पांच स्तरीय प्रशिक्षण व्यवस्था से तैयार होंगे जनगणना कर्मी

जनगणना कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए पांच स्तरीय प्रशिक्षण व्यवस्था बनाई गई है। राष्ट्रीय प्रशिक्षकों, मास्टर ट्रेनर्स तथा जिला एवं चार्ज अधिकारियों का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। फील्ड ट्रेनर्स के लिए 2 से 12 दिसंबर तक जिला मुख्यालयों में तीन दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। इसके बाद 21 दिसंबर 2026 से 15 जनवरी 2027 तक प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों को चार्ज स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाएगा।

डिजिटल एप एवं पोर्टल से होगी निगरानी

जनगणना के लिए विशेष मोबाइल एप विकसित किया गया है, जो 16 भाषाओं में उपलब्ध होगा। इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होने पर भी एप के माध्यम से ऑफलाइन जानकारी दर्ज की जा सकेगी। जनगणना प्रबंधन एवं निगरानी प्रणाली (सीएमएमएस) पोर्टल के माध्यम से गणना ब्लॉकों का गठन, कार्य आवंटन, प्रशिक्षण एवं कार्यों की निगरानी की जाएगी। नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी की गोपनीयता एवं सुरक्षा के लिए पासवर्ड, ओटीपी और डेटा एन्क्रिप्शन जैसी तकनीकों का उपयोग किया जाएगा।

जनजागरूकता अभियान से बढ़ेगी नागरिकों की सहभागिता

जनगणना के प्रति नागरिकों में जागरूकता एवं विश्वास बढ़ाने के लिए दिसंबर 2026 के मध्य से 28 फरवरी 2027 तक व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। विभिन्न विभागों के सहयोग से जनगणना की प्रक्रिया, प्रमुख तिथियों एवं व्यक्तिगत जानकारी के संबंध में जन सामान्य को अवगत कराया जाएगा। जनगणना के सफल संचालन के लिए विभागीय समन्वय, नियमित निगरानी, तकनीकी सहयोग, आंकड़ों के सत्यापन पर विशेष जोर दिया गया है।

25 जनवरी से 28 फरवरी 2027 तक घर-घर जाकर जनसंख्या गणना करेंगे

छत्तीसगढ़ के जनगणना निदेशक कार्तिकेय गोयल ने प्रथम चरण में मकान सूचीकरण के तहत किए गए कार्यों की जानकारी देते हुए द्वितीय चरण की कार्ययोजना का प्रस्तुतीकरण किया। उन्होंने बताया कि जनसंख्या गणना का कार्य पूरी तरह डिजिटल माध्यम से किया जाएगा। इसके अंतर्गत 10 से 24 जनवरी 2027 तक स्व-गणना की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इसके बाद 25 जनवरी से 28 फरवरी 2027 तक प्रगणक घर-घर जाकर जनसंख्या गणना करेंगे। एक से पांच मार्च 2027 तक पुनरीक्षण कार्य किया जाएगा। स्व-गणना के दौरान नागरिकों द्वारा स्वयं जानकारी दर्ज करने पर एक आईडी जनरेट होगी, जिसे प्रगणक को उपलब्ध कराना होगा। स्व-गणना ऐच्छिक है जरूरी नहीं।

प्रधानमंत्री आवास योजना से जरूरतमंद परिवारों के अपने घर का सपना हो रहा पूरा

मंजू भगत के पक्के घर का सपना हुआ साकार, मुख्यमंत्री साय ने कराया गृह प्रवेश

श्रीकंचनपथ समाचार



रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जशपुर जिले के कुनकुरी विकासखंड अंतर्गत ग्राम जोकरी में प्रधानमंत्री आवास योजना की हितग्राही मंजू भगत के नवनिर्मित पक्के आवास का फीता काटकर गृह प्रवेश कराया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने परिवार के सदस्यों से आत्मीय मुलाकात की और उनके नए घर की खुशियों में सहभागी बने।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हर जरूरतमंद परिवार का अपना पक्का घर हो, यह हमारी सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि किसी परिवार के लिए अपना घर केवल चारदीवारी और छत नहीं, बल्कि सुरक्षा, सम्मान और बेहतर भविष्य का आधार होता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से ऐसे लाखों परिवारों के सपने साकार हो रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जब किसी जरूरतमंद परिवार को अपना पक्का घर मिलता है और परिवार की महिला उस घर की मालकिन बनती है, तो यह खुशी और भी बढ़ जाती है। यह महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तीकरण की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है।

श्रीमती मंजू भगत के परिवार के लिए यह अवसर विशेष खुशी का रहा। वर्षों से संजोया अपना पक्का घर होने का सपना पूरा होने पर परिवार के सदस्यों में उत्साह दिखाई दिया। मुख्यमंत्री साय ने मंजू भगत एवं उनके परिजनों को नए आवास की बधाई देते हुए कामना की कि उनका यह घर सदैव सुख, शांति और समृद्धि से भरा रहे। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री साय ग्राम जोकरी में आयोजित प्रांतीय चीक-चिक जाति उत्थान समिति के सामाजिक सम्मेलन एवं सांस्कृतिक महोत्सव में शामिल होने पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना की हितग्राही के घर पहुंचकर गृह प्रवेश कराया।

एक भारत-श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम हमारी विविधता को एकता के सूत्र में पिरोने का सशक्त माध्यम- राज्यपाल डेका

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका के मुख्य आतिथ्य में लोकभवन में 7 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर राज्यपाल रमेन डेका ने कहा कि यह आयोजन केवल राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना दिवस मनाने का अवसर नहीं, बल्कि उनकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, गौरवशाली इतिहास, परंपराओं और विकास यात्रा को जानने-समझने तथा आपस में जुड़ने का माध्यम है।

यह आयोजन हमारी विविधता को एकता के सूत्र में पिरोने और राष्ट्रीय एकता की भावना को सुदृढ़ करने का संदेश देता है।

राज्यपाल ने कहा कि हमारी भाषाएं, संस्कृतियां, परंपराएं और भौगोलिक विशेषताएं भले ही अलग-अलग हों, लेकिन हमारी राष्ट्रीय पहचान एक है। उन्होंने देश की रियासतों को एकजुट कर अखंड भारत के निर्माण में सरदार वल्लभभाई पटेल के ऐतिहासिक योगदान का स्मरण किया। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री स्व अटल बिहारी वाजपेयी की दूरदर्शी सोच से छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ। छत्तीसगढ़ के बारे में लोग सोचते थे कि यह नक्सली राज्य है और यहां शांति नहीं है। लेकिन अब प्रदेश की पहचान बदल चुकी है। केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से बस्तर क्षेत्र में नक्सलवाद का प्रभाव समाप्त हो गया है और प्रदेश शांति, सुरक्षा तथा विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। बस्तर में बच्चे स्कूल जा रहे हैं, संस्थागत प्रसव हो रहे हैं,विकास की गतिविधियां बढ़ रही हैं और डिजिटल सुविधाएं लोगों तक पहुंच रही हैं।

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ प्राकृतिक सौंदर्य, समृद्ध संस्कृति और विशिष्ट परंपराओं वाला प्रदेश है। ऐतिहासिक विरासत का उल्लेख करते हुए उन्होंने उज्जैन की धार्मिक महत्ता तथा ग्वालियर के ऐतिहासिक गुरुद्वारा , सेना में सिख, सैनिकों की वीरता तथा स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान का उल्लेख किया।

गांवों तक बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हमारी सरकार की प्राथमिकता : साय

मुख्यमंत्री साय ने जशपुर को दी 33.78 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की सौगात, एक उच्चस्तरीय पुल और दो विद्युत उपकेंद्रों का लोकार्पण, चार नए उच्चस्तरीय पुलों का भूमिपूजन

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जशपुर जिले के कुनकुरी विकासखंड अंतर्गत ग्राम जोकरी में आयोजित कार्यक्रम में जिलेवासियों को 33 करोड़ 78 लाख रुपये के विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने एक उच्चस्तरीय पुल तथा दो विद्युत उपकेंद्रों का लोकार्पण करने के साथ ही चार नए उच्चस्तरीय पुलों के निर्माण कार्यों का भूमिपूजन किया। इन विकास कार्यों से जिले के दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में आवागमन की सुविधाओं का विस्तार होगा और बिजली आपूर्ति व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।



मुख्यमंत्री साय ने इस अवसर पर कहा कि गांवों का विकास ही प्रदेश की समृद्धि का आधार है। हमारी सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, पुल-पुलिया, बिजली और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि नदी-नालों पर पुलों के निर्माण से बरसात के दिनों में आवागमन की कठिनाइयां दूर होंगी। ग्रामीणों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और व्यापार के लिए जिला एवं विकासखंड मुख्यालयों तक पहुंचने में सुविधा होगी।

मुख्यमंत्री साय ने नारायणपुर-गौता-रजौटी मार्ग पर डोड़की नदी में 6 करोड़ 55 लाख 53 हजार रुपये की लागत से निर्मित 120 मीटर लंबे उच्चस्तरीय पुल का लोकार्पण किया। इस पुल से आसपास के लगभग 10 गांवों की 7,471 आबादी लाभान्वित होगी। पुल के निर्माण से ग्रामीणों को वर्षभर सुगम आवागमन की सुविधा मिलेगी। विशेष रूप से बरसात के मौसम में नदी के कारण होने वाली आवागमन की कठिनाइयों से राहत मिलेगी।

मुख्यमंत्री साय ने जिले के विभिन्न ग्रामीण मार्गों पर 22 करोड़ 77 लाख 31 हजार रुपये की लागत से बनने वाले चार उच्चस्तरीय पुलों एवं पहुंच मार्गों का भूमिपूजन किया। इनमें रेंगारघाट-कुड़केला मार्ग पर बोलजोरा में 4 करोड़ 47 लाख 98 हजार रुपये की लागत से 92 मीटर लंबे उच्चस्तरीय पुल का निर्माण किया जाएगा। इससे लगभग 6,500 ग्रामीण लाभान्वित होंगे। इसी प्रकार बोड़ाकछार-चटकपुर मार्ग पर चंपाझरिया में 4 करोड़ 46 लाख 58 हजार रुपये की लागत से 100 मीटर लंबे उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण होगा। इससे लगभग 3,519 ग्रामीणों को बेहतर आवागमन की सुविधा मिलेगी। बसेनताला-चटकपुर मार्ग पर सिंधु नाला में 2 करोड़ 55 लाख 72 हजार रुपये की लागत से 63 मीटर लंबे उच्चस्तरीय पुल का निर्माण किया जाएगा। इससे आसपास के गांवों की लगभग 6,133 आबादी लाभान्वित होगी। इसके अतिरिक्त ठेठेटांगर-चोंगरीबहार मार्ग पर ईब नदी में 11 करोड़ 27 लाख 3 हजार रुपये की लागत से 312 मीटर लंबे उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण होगा। इस पुल से क्षेत्र के लगभग 6 हजार ग्रामीणों को बारहमासी आवागमन की सुविधा मिलेगी। इन चारों पुलों के निर्माण से दूरस्थ गांवों की मुख्य मार्गों से कनेक्टिविटी बेहतर होगी। ग्रामीणों को दैनिक आवागमन के साथ कृषि उपज के परिवहन, व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने में सहूलियत होगी। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि विकास की सार्थकता तभी है, जब उसका लाभ दूरस्थ गांवों और अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचे। सड़क और पुल केवल आवागमन के साधन नहीं हैं, बल्कि गांवों की प्रगति और नए अवसरों के द्वार भी हैं। इसी तरह बेहतर बिजली व्यवस्था ग्रामीण जीवन को सुविधाजनक बनाने के साथ आर्थिक गतिविधियों को नई गति देती है।

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और संतुलित विकास के लिए प्रतिबद्ध है। जशपुर सहित प्रदेश के दूरस्थ अंचलों में विकास कार्यों को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है, ताकि ग्रामीणों का जीवन अधिक सुगम, सुरक्षित और सुविधाजनक बन सके।

इस अवसर पर कलेक्टर रोहित व्यास, पुलिस अधीक्षक लाल उमेद सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष सालिक साय, प्रबल प्रताप सिंह जूदेव, चीक बड़ाईक महासभा के सत्यनारायण बड़ाईक, ग्राम पंचायत जोकरी की सरपंच मंजू भगत, पूर्व विधायक रोहित कुमार साय, वरिष्ठ जनप्रतिनिधि उपेंद्र यादव सहित समाज के प्रमुख पदाधिकारी, जनप्रतिनिधिगण, जिला प्रशासन के अधिकारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे।

काईकछार और बालाछापर में विद्युत उपकेंद्रों का लोकार्पण

मुख्यमंत्री साय ने ग्राम काईकछार एवं बालाछापर में कुल 4 करोड़ 45 लाख रुपये की लागत से निर्मित 33/11 केवी क्षमता के दो विद्युत उपकेंद्रों का लोकार्पण भी किया। इन उपकेंद्रों के प्रारंभ होने से आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत वितरण व्यवस्था सुदृढ़ होगी। बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार के साथ उपभोक्ताओं को अधिक सुचारु विद्युत सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध बिजली आपूर्ति से न केवल घरेलू उपभोक्ताओं को सुविधा मिलेगी, बल्कि खेती-किसानी, छोटे व्यवसायों और अन्य आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक राजेश अग्रवाल द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि. छत्तीसगढ़ भवन, प्रेस काम्पलेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) से मुद्रित कर, 204 आकाशगंगा सुपेला, भिलाई जिला दुर्ग (छ.ग.) से प्रकाशित। संपादक राजेश अग्रवाल shreekanchanpath2010@gmail.com, Mo - 9303289950